

तमिलनाडु : भाजपा छोड़ेंगे अन्नामलाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और दक्षिण में पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक के अन्नामलाई मंगलवार को भाजपा से अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और औपचारिक रूप से दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपने फैसले से अवगत करा सकते हैं।



भाजपा के विश्वसनीय सूत्रों ने सोमवार को बताया कि उन्होंने अपना मन बना लिया है और दिल्ली का यह दौरा महज एक राजनीतिक बैठक नहीं बल्कि उस पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करने का भी एक तरीका है जिसके साथ उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के पिछले छह साल बिताए हैं। उधर, अन्नामलाई ने पार्टी से नाराजगी और नया राजनीतिक संगठन बनाने की संभावनाओं को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर

बाकी पेज 8 पर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण के अधिकांश प्रावधानों को अंतिम रूप दे दिया है और अब बातचीत कुछ छोटे मुद्दों तक ही केंद्रित है। गोयल ने कहा कि लगभग सभी चीजें तय हो चुकी हैं। जैसा कि अमेरिकी राजदूत ने भी कहा है कि 99 फीसद मुद्दों पर सहमति बन चुकी है।

गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए भारत में है। दोनों पक्षों के बीच दो से चार जून तक यह



बातचीत होगी। इस वार्ता में बाजार पहुंच, गैर-शुल्क बाधाएं, सीमा शुल्क, निवेश प्रोत्साहन और आपूर्ति शृंखला से जुड़ी रणनीतिक साझेदारी पर गहन चर्चा हो रही है।

इस उच्च स्तरीय वार्ता में दोनों देशों की टीमों तकनीकी विवरणों को सुलझाने और कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। दोनों देशों ने तीन फरवरी को

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत में, चार जून तक होगी बातचीत। इस वार्ता में बाजार पहुंच, गैर-शुल्क बाधाएं, सीमा शुल्क, निवेश प्रोत्साहन और आपूर्ति शृंखला से जुड़ी रणनीतिक साझेदारी पर गहन चर्चा हो रही है।

दोनों देशों ने तीन फरवरी को इस व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए रूपरेखा तय होने की घोषणा की थी।

इस व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए रूपरेखा तय होने की घोषणा की थी। गोयल ने कहा कि अब केवल छोटे-छोटे बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देते समय इस पर भी विचार किया जा रहा है कि अमेरिका में हुए कानूनी बदलावों को इसमें किस तरह से जगह दी जाएगी। उन्होंने

बाकी पेज 8 पर

व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 42 रुपए महंगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

होटल और रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाली व्यावसायिक द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत राजधानी दिल्ली में सोमवार को 42 रुपए बढ़ा दी गई। अब दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3,071.50 रुपए से बढ़कर 3,113.50 रुपए हो गई है।

यह वृद्धि एक मई को की गई 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी के बाद हुई है, जिससे व्यावसायिक एलपीजी कीमतें रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। वहीं कोलकाता में व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में 53.50 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। यहां अब ये सिलेंडर 3,255.50 रुपए में मिलेगा। पहले ये 3,202 रुपए में मिल रहा था। वहीं, पांच किलोग्राम 'फ्री-ट्रेड' एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी 11 रुपए बढ़ाकर 821.50 रुपए कर दी गई



पांच किलोग्राम 'फ्री-ट्रेड' सिलेंडर की कीमत भी 11 रुपए बढ़ाकर 821.50 रुपए की गई। धरतू गैस के दाम जस के तस। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एटीएफ हुआ 27 फीसद सस्ता।

है। इसे कोई भी बिना आवास पता प्रमाण के ले सकता है। पांच किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर को नियमित कनेक्शन के साथ लेने पर इसका दाम 339 रुपए पर स्थिर है।

घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। 14.2 किलोग्राम के

बाकी पेज 8 पर

'भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा'

नई दिल्ली, 1 जून (ब्यूरो)।

म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हवाई में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ उनके देश की धरती का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा।

दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में द्विपक्षीय

प्रधानमंत्री मोदी से मिले म्यांमा के राष्ट्रपति आंग हवाई।

बाकी पेज 8 पर



नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हवाई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

सीबीएसई : पुनर्मूल्यांकन पोर्टल दिन भर नहीं चला, विद्यार्थी रहे हलकान

नई दिल्ली, 1 जून (ब्यूरो)।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने की घोषित तिथि के बाद भी सोमवार को दिन भर पोर्टल नहीं खुला। सीबीएसई के आधिकारिक पोर्टल पर लगातार 'रखरखाव के अधीन' संदेश प्रदर्शित होता रहा। इससे हजारों विद्यार्थी हलकान रहे।

सीबीएसई सूत्रों ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल जल्द चालू होने की उम्मीद है।

-पूरी खबर पेज 8 पर

तृणमूल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर दो विधायकों को निकाला

नई दिल्ली, 1 जून (ब्यूरो)।

तृणमूल कांग्रेस ने कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर अपने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को सोमवार को निष्कासित कर दिया।

निष्कासन आदेश से कुछ ही मिनट पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा था कि राज्य विधानसभा में 'फर्जी हस्ताक्षर' मामले के संबंध में शिकायतें इन दोनों विधायकों ने दर्ज कराई थीं।

-पूरी खबर पेज 12 पर

पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने रवनीत बिट्टू को चार जून को तलब किया

चंडीगढ़, 1 जून (ब्यूरो)।

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कथित जातिसूचक टिप्पणी के मामले में चार जून को पेश होने के लिए सोमवार को समन जारी किया।

आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया कि बिट्टू ने हाल में धूरी में वैसे के दौरान कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था।

-पूरी खबर पेज 10 पर

HDFC
MUTUAL FUND
भरोसा अपनों का

फलैक्सि कैप फंड्स

मौके बनाए मुमकिन

जिंदगी के लिए SIP

फलैक्सि कैप फंड्स के फायदे

मौकों का फायदा उठाने के लिए लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स में एक से दूसरे में जाने की आज़ादी

मार्केट की दशाओं के अनुसार एडजस्ट करें

लंबी अवधि के निवेशकों के लिए उपयुक्त

अधिक जानने के लिए स्कैन करें

निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान | SIP - सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान.

म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, वन टाइम KYC की आवश्यकता को पूरा करने की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी हेतु <https://www.hdfcfund.com/information/key-know-how> पर विजिट करें. निवेशकों को केवल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, जिनके विवरण का सत्यापन सेबी की वेबसाइट (www.sebi.gov.in/intermediaries.html) पर किया जा सकता है. किसी पूछताछ, शिकायत तथा समस्या के समाधान के लिए निवेशक एमसीज तथा/या निवेशक संपर्क अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. इसके साथ ही, निवेशक एमसीज को सीधे भी शिकायत कर सकते हैं, अगर वे एमसीज द्वारा दिए गए समाधान से संतुष्ट न हों तो वे स्कोर्स पोर्टल <https://scores.sebi.gov.in> पर भी शिकायत कर सकते हैं. स्कोर्स पोर्टल निवेशकों को सेबी की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने तथा तत्पश्चात इसकी स्थिति को देखने की सुविधा प्रदान करता है. अगर निवेशक सीधे एमसीज से की गई या स्कोर्स पोर्टल के जरिए दर्ज शिकायतों पर समाधान से संतुष्ट न हों तो वह स्मार्ट ओडीआर पर <https://smartodr.in/login> शिकायत दर्ज कर सकता है. इस सामग्री में दिखाए गए चर्चों और/या सचित्र उदाहरणों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, केवल समझाने तथा जानकारी देने के प्रयोजन से बनाया गया है.

HDFC Mutual Fund: SEBI Registration Number: MF/044/00/6

अधिक जानकारी के लिए एमएफडी/आरआईए से संपर्क करें | एसआईपीज के बारे में जानें hdfcfund.com/sip

म्यूचुअल फंड निवेश बाज़ार के जोखिमों के अधीन हैं, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।



नई दिल्ली राजधानी

खबर कोना

नकदी और आभूषण चुराने का आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

हौज काजी इलाके में एक घर से पौने चार लाख रुपए की नकदी और गहने चुराने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि आरोपी अरशद अली के पास से चोरी के 1.80 लाख रुपए नकद और अन्य माल बरामद कर लिया गया है। मध्य दिल्ली के पुलिस उपकुल रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि अली पहले भी चोरी के पांच मामलों में शामिल रहा है। उनके अनुसार, 30 मई को हौज काजी थाने में चोरी की एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 29 मई की शाम वह अपनी पत्नी के साथ कहीं गए थे और जब लौटे, तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला, जहां से 3,75,000 रुपए नकद और सोना, चांदी व 'आर्टिफिशियल' आभूषण गायब थे।

हत्या के मामले में नौ साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

दिल्ली पुलिस ने 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी और संपत्ति के लिए एक महिला की हत्या के मामले में नौ साल से फरार आरोपी को बिहार के लखीसराय से गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इस मामले में एक अन्य आरोपी की 2018 में मृत्यु हो गई थी। पुलिस के अनुसार, चंदन कुमार को 29 मई को लखीसराय से गिरफ्तार किया गया है। अपराध शाखा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुराड़ी थाने में दर्ज हत्या के मामले में चंदन कुमार को 2018 में भगोड़ा घोषित किया गया था। पुलिस ने बताया कि चंदन, अपने भाई कुंदन कुमार और अपने रिश्तेदार कमल कुमार के साथ अगस्त 2017 में 43 वर्षीय अमोता देवी की हत्या में कोषित तौर पर शामिल था।

पाक्सो मामले में अदालत की कार्रवाई आठ दिन के भीतर सुनवाई पूरी, दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

दिल्ली की एक अदालत ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में आठ दिनों में सुनवाई पूरी कर ली और 38 वर्षीय दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, इस साल 17 अप्रैल को जब प्राथमिकी दर्ज की गई थी तब लड़की 32 सप्ताह की गर्भवती थी। उसने आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी ने जुलाई 2025 में कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया था। पुलिस ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद के बाद 34 दिनों के भीतर अदालत में आरोप-पत्र दाखिल कर



पीड़ित के लिए 16.5 लाख रुपए का मुआवजा भी स्वीकृत किया गया है।

दिया गया, अदालत ने आठ दिनों में सुनवाई पूरी की, 29 मई को आरोपी को दोषी ठहराया और 30 मई को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने यह भी बताया कि पीड़ित के लिए 16.5 लाख रुपए का मुआवजा भी स्वीकृत किया गया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी का घर उसके घर के ठीक सामने था



आक्रोश

नई दिल्ली में नीट पेपर लीक प्रकरण और सीयूईटी परीक्षा स्थगन के मामले में प्रदर्शन करते आइसा और केवाईएस के सदस्य।

और वह परिवार का परिचित था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता का आरोप था कि पहले उसके भाई-बहनों को पास की दुकान पर भेजा गया, जिसके बाद उसपर यौन-हमला किया गया तथा उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। मामला तब सामने आया जब पीड़िता गर्भवती पाई गई और उसने अपनी मां को यौन उत्पीड़न के बारे में बताया।

नाबालिग ने 17 अप्रैल को अपने माता-पिता के साथ पुलिस से शिकायत की। पीड़िता के बयान के आधार पर उसी दिन बाहरी दिल्ली के निहाल विहार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, अदालत ने स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास के तहत दोषी को उसके शेष जीवनकाल तक जेल में रहना होगा।

'फसलों के नुकसान पर मिलेगा 75 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

दिल्ली सरकार ने फसलों के नुकसान होने पर किसानों को दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। सोमवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली सरकार ने इस बाबत मंजूरी दे दी है। अगस्त-सितंबर 2025 के दौरान भारी वर्षा व खेतों में जलभराव से प्रभावित किसानों को अब 75 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा सरकार देगी। सरकार के इस निर्णय से दिल्ली के करीब दस हजार किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में कुल 10,977.44 एकड़ यानि लगभग 4,442.41 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ था। वर्ष 2015 में तत्कालीन सरकार द्वारा वर्षा से फसल क्षति की स्थिति में किसानों को 20 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने का प्रावधान था। यह राशि लगभग 49,421 रुपए प्रति हेक्टेयर है।

लेकिन हमारी सरकार ने दस वर्षों से अधिक समय की अवधि में कृषि लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सहायता की दर बढ़ाकर 75 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया है। इससे पहले की तुलना में किसानों को अधिक सहायता प्राप्त होगी। यह सहायता भूमि के अभिलेखित स्वामियों को दी जाएगी। कंपनियों के स्वामित्व वाली भूमि, ग्राम सभा में निहित भूमि तथा पक्की चारदीवारी वाले भूखंड स्वरूप के फार्महाउस इस सहायता के दायरे में शामिल नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा कराए गए विस्तृत आंकलन में पाया गया कि अगस्त-सितंबर 2025 की भारी वर्षा और खेतों में जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा और फसल क्षति का आंकलन 100 फीसद किया गया। उन्होंने कहा कि यह सहायता किसानों को आर्थिक संतुलन प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें अगली फसल की तैयारी में सक्षम बनाएगी और कृषि गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करेगी।

समिति ने चिकित्सकों के संगठन को अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी

नई दिल्ली, 1 जून (संवाददाता)।

नीट-यूजी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में आमंत्रित यूनाइटेड डाक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) के प्रतिनिधियों को अंतिम समय में शामिल होने और अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी गई। संगठन ने इसका विरोध जताया है।

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में

यूडीएफ को समिति की बैठक के लिए एक सप्ताह पहले औपचारिक निमंत्रण भेजा गया था और एजेंडा में भी उसका उल्लेख था। हालांकि संसद पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि वे बैठक की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। संगठन के अनुसार, समिति के कुछ सांसदों के

विरोध के कारण उन्हें शामिल नहीं किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष विग्वजय सिंह ने यूडीएफ प्रतिनिधियों से मुलाकात कर चिकित्सा छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित न कर पाने पर खेद जताया।

उन्होंने संगठन के सुझाव-पत्र को रिकार्ड में लेने का आश्वासन भी दिया। यूडीएफ अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्य मित्तल ने कहा कि राष्ट्रीय महत्त्व की परीक्षा से जुड़े मामलों में

हितधारकों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। यूडीएफ ने अपने ज्ञान में एनटीए को भंग कर नई परीक्षा एजेंसी बनाने तथा नीट-यूजी 2024 और 2026 से जुड़े मुद्दों, पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स, परीक्षा सुरक्षा और अन्य विवादों की व्यापक जांच की मांग की है।

जम्मू-कश्मीर विस्थापितों के लिए अचल संपत्ति और आय की शर्तें हटीं

नई दिल्ली, 1 जून (संवाददाता)।

जम्मू-कश्मीर से विस्थापित होकर दिल्ली में रह रहे प्रवासी परिवारों के कल्याण, पुनर्वास व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार ने उन्हें प्रदान की जाने वाली तदर्थ मासिक राहत योजना (एमआर) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सोमवार को मंजूरी दी है।

यह योजना केवल उन पंजीकृत प्रवासी परिवारों पर लागू होगी, जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक राहत प्राप्त की है। बता दें कि, इस निर्णय के बाद उन्हें उनकी आय संबंधी पात्रता की शर्त को समाप्त करने का निर्णय लिया है। जिससे अब परिवार की आय कितनी भी हो या उसके पास कोई अचल संपत्ति हो, इससे राहत प्राप्त करने की पात्रता प्रभावित नहीं होगी।

माडल टाउन, मुखर्जी नगर और चांदनी महल थाना क्षेत्र की घटना

दो लोगों की चाकू व एक की कैची घोंप कर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ घंटों के भीतर तीन लोगों की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। पहली घटना माडल टाउन थाना क्षेत्र की है, जहां पर 25 वर्षीय साहिल की हत्या की गई। दूसरी घटना मुखर्जी नगर थाना क्षेत्र की है, जहां पर 38 वर्षीय दिलबहार की सहकर्मी ने हत्या कर दी। वहीं, चांदनी महल थाना क्षेत्र में कुछ हमलावरों ने 50 वर्षीय कामिल को हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों ही मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

उत्तरी पश्चिमी जिला उपायुक्त आकांक्षा यादव ने सोमवार को बताया कि विनायक अस्पताल से रिविचर को सूचना मिली कि बुराड़ी के तोमर कालोनी निवासी साहिल को उसके दोस्त शिव और शुभम गंभीर अवस्था में लेकर आए थे, जिसे

चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। साहिल के सीने, पीट और गर्दन पर चाकू से वार किए जाने के कई निशान थे। जांच में पता चला कि घटना एमसीडी कालोनी में हुई थी। चरमदीय शिव के मुताबिक लालबाग निवासी 18 वर्षीय आशु उर्फ लाला ने साहिल पर चाकू से वार किए थे। वारदात में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में माडल टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।

वहीं, मुखर्जी नगर थाना पुलिस को सोमवार को सूचना मिली कि एक शख्स पर उसके कर्मचारी ने हमला किया है। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि घायल को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने 38 वर्षीय दिलबहार को मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला कि वह पेंटल चैट अस्पताल के बाहर गदा

बनाने का काम करता था। उसके साथ काम करने वाला अशफाक उर्फ शहबाज से उसकी कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद आरोपी ने दिलबहार पर कैची से कई बार वार कर दिया और मौके से फरार हो गया। हालांकि, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी अशफाक को दबोच लिया है।

मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने सोमवार को बताया कि चांदनी महल थाना क्षेत्र में चाकू मारे जाने की सूचना रिविचर देर रात करीब 11:30 बजे मिली थी। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि घायल शख्स की मौत हो चुकी है। दरअसल, कामिल अपनी 27 वर्षीय बेटी और छह साल की नातिन के साथ झुलावाले के पास गए थे। उसकी नातिन झुला झूल रही थी, तभी दो लड़के वहां आए और लूटपाट करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने कामिल पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हत्या का मामला दर्ज कर दो नाबालिगों को पकड़ा गया है।

वर्षा जल संचयन के लिए बनाए जाएंगे 500 नए ढांचे

नई दिल्ली, 1 जून (संवाददाता)।

दिल्ली जलबोर्ड ने राजधानी में व्यापक वर्षा जल संचयन अभियान शुरू किया है ताकि मानसून से पहले जल सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही भूजल स्तर में सुधार लाया जा सके।

इस अभियान के प्रथम चरण में जलबोर्ड 500 नए वर्षा जल संचयन ढांचों का निर्माण करेगा तथा विभिन्न सरकारी भवनों में स्थापित एक हजार निष्क्रिय प्रणालियों को पुनः कार्यशील बनाएगा।

डीयू की आपत्तियों के बावजूद सेंट स्टीफंस कालेज की प्राचार्य ने कार्यभार संभाला

नई दिल्ली, 1 जून (संवाददाता)।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की आपत्तियों के बावजूद सेंट स्टीफंस कालेज ने प्राचार्य की नियुक्ति कर दी। सुजेन एलियास ने सोमवार को कालेज के 14वें प्राचार्य के रूप में कार्यभार संभाल लिया।

कालेज ने इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की लेकिन सूत्रों ने यह जानकारी दी। कालेज की सुप्रीम काउंसिल ने एलियास की नियुक्ति 12 मई को ही एक अधिसूचना के माध्यम से कर दी थी, जिसके बाद डीयू ने कालेज को पत्र लिखकर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया था और दावा किया था कि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों का उल्लंघन है। पदभार ग्रहण करने के सवाल पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। वे यूजीसी से आगे के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।

सार्वजनिक सूचना

सभी संबंधितों को यह नोटिस दिया गया है और आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि कंपनी को प्रस्तावित वाणिज्यिक भवन का निर्माण के लिए 21/37/2025-आईए-III दिनांक 27/05/2026 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ("एमओईएफ") द्वारा पर्यावरण मंजूरी जारी की गई है। प्लॉट संख्या एलपी-03-02, एयरोसिटी डायनटाउन डिस्ट्रिक्ट, एयरोसिटी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। उक्त पर्यावरण मंजूरी की प्रतियां एमओईएफसीसी/एसईआईएए परिवेश पोर्टल की वेबसाइट पर उपलब्ध है <https://parivesh.nic.in>

Sd/-
M/s PAMIR DEVELOPERS LIMITED
3rd Floor, Worldmark 2, Asset 8, Aerocity, New Delhi-110037
Phone No.: 011-41384000



DABUR INDIA LIMITED

CIN: L24230DL1975PLC007908
Regd. Off: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002
Phone: 011-23253488, Website: www.dabur.com,
Email: investors@dabur.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL SECURITIES

In terms of SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 dated January 30, 2026 on the above-referred subject matter, please note that Special Window has been opened for a period of one year from February 5, 2026 to February 4, 2027, allowing shareholders to lodge/re-lodge transfer and dematerialization requests of physical securities which were sold/purchased prior to April 1, 2019 but were not lodged with the Company/RTA or rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise.

Eligible Shareholders who wish to avail this opportunity are advised to contact the Company's Registrar to an Issue & Share Transfer Agent (RTA) KFin Technologies Limited at their address, Unit: Dabur India Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500032, Telangana or at their email address at inward.ris@kfinetech.com or send an email to the Company at investors@dabur.com at the earliest so as to enable the Company/RTA to complete the transfer / demat process on or before the deadline of February 4, 2027.

June 01, 2026
New Delhi

For DABUR INDIA LIMITED
(SAKET GUPTA)
Company Secretary

FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead

HONOURING THE BANKS THAT INDIA CAN BANK ON.

JUNE 7 2026 MUMBAI

IRB
INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD
HIGHWAY TO GROWTH

presents

INDIA'S BEST BANKS AWARDS

co-presented by

NxtGen¹

Chief Guest

Piyush Goyal

Hon'ble Union Minister of
Commerce & Industry

Corporate Partner

TAPMI

Associate Partners

RUNWAL REALTY

NYATI

Knowledge Partner

EY
Shape the future with confidence

Live Streaming @financialexpress

febestbanksawards.com

खबर कोना

गुरुग्राम : महिला का सड़ा गला शव शौचालय में मिला
गुरुग्राम, 1 जून (भाषा)।

गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 इलाके में दूसरी मंजिल पर स्थित एक घर के शौचालय में 74 वर्षीय महिला का सड़ा गला शव बरामद हुआ। पुलिस ने सोमवार को बताया कि महिला की पहचान रीता बख्शी के रूप में हुई है जो अपनी बेटी रजनी बख्शी के साथ उसी घर में रहती थीं। रजनी ने 28 मई को डीएलएफ फेज 2 थाने में अपनी मां के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी मां 25 मई से लापता हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस दो बार उनके घर गई लेकिन महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पड़ोसियों ने 30 मई की शाम को पुलिस को घर से दुर्गंध आने की सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां शौचालय में रीता बख्शी का शव सड़ी-गली अवस्था में मिला। पुलिस को संदेह है कि बुर्गामी महिला शौचालय में फिसलकर गिर गई, जिससे उनके सिर में चोट आई और उनकी मृत्यु हो गई।

‘दाखिले के नाम पर ठगी करने वालों से बचकर रहें’
जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आइपी) में दाखिले का झांसा देने वाले धोखेबाज सक्रिय हैं। विश्वविद्यालय का कहना है कि इस बाबत कई उम्मीदवारों ने की शिकायत की है। इसके बाद विश्वविद्यालय ने धोखेबाजों को लेकर आवेदकों को सतर्क करना पड़ा है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में उसने कहा कि उसे ऐसे कई उम्मीदवारों से शिकायतें मिली हैं जिससे कथित धोखेबाजों ने दाखिले के लिए संपर्क किया। विश्वविद्यालय की प्रवक्ता नलिनी रंजन ने कहा कि विश्वविद्यालय ने सभी आवेदकों से कहा है कि वे ऐसे संदेशों के झांसे में न आए और यदि कोई एजेंट इस उद्देश्य से उनसे संपर्क करता है तो विश्वविद्यालय को सूचित करें।

यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 20 केंद्रों पर होगी
जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 1 जून।

आठ से 10 जून तक होने वाली यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस लिखित परीक्षा में 42048 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए जनपद में 20 केंद्र बनाए गए हैं। नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा के लिए बायोमीट्रिक सत्यापन, चेहरा मिलान और लाइव सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। हालांकि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की जांच के दौरान कलावा और मंगलसूत्र नहीं उतरवाए जाएंगे। परीक्षा रोजना दो पाली में होगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को तय समय से पहले केंद्रों पर पहुंचना होगा, ताकि जांच और सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मचारी और शिक्षक भी केंद्र के भीतर अपना मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे।

नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले तीन दबोचे
जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

पुरानी दिल्ली रेलवे थाना पुलिस और रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम ने भारतीय रेलवे में एमटीएस और लिपिक की नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान ईशा, रणजीत और आलम के तौर पर की गई है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने पीड़ित की ओर से दिए गए 3,60,000 रुपये जब्त किए हैं। रेलवे पुलिस उपायुक्त बी बोम्मा रेड्डी ने सोमवार को बताया कि पीड़ित ने पुरानी दिल्ली रेलवे थाना पुलिस से संपर्क किया और बताया कि उससे भारतीय रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी की गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक योजना बनाई और बाकी के रकम लेने के लिए आरोपी को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बुलाया। टीम ने सबसे पहले ईशा को चान्दनी चौक के गेट नंबर-3 के पास से गिरफ्तार किया।

साकेत हादसा : मकान मालिक गिरफ्तार, बचाव कार्य पूरा

मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलाजाब इलाके में शनिवार को ढह गई थी बहुमंजिला इमारत, छह लोगों की गई थी जान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

दक्षिणी दिल्ली के साकेत इलाके में शनिवार को ढही बहुमंजिला इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि आठ अन्य घायल हुए थे। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि आरोपी कर्मवीर उस इमारत का मालिक है, जो साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलाजाब इलाके में शनिवार को ढह गई थी। वहीं, इमारत ढहने के स्थल पर बचाव और मलबा हटाने का कार्य भी सोमवार को पूरा कर लिया गया। एहतियातन मौके पर आपातकालीन दल तैनात रहे। इस इमारत में एक कोचिंग सेंटर, कैफे और कार्यालय थे। पुलिस ने बताया कि अधिकतर पीड़ित छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी थे जिनमें विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) की तैयारी करने वाले भी शामिल थे। घायलों में से पांच ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य की सफुदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। यह घटना सैद-उल-अजैब इलाके में



आप नेताओं ने किया प्रदर्शन, उपायुक्त के इस्तीफे की मांग
आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने साकेत में इमारत ढहने की घटना को लेकर सोमवार को दक्षिणी दिल्ली के उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया उपायुक्त राकेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी क्षेत्र के पार्षदों ने जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। अवैध इमारत को लेकर उपायुक्त को बार-बार शिकायतें भेजी गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

वेस्टएंड मार्ग पर शाम सात बजकर 40 मिनट पर हुई। इस इलाके में पुरनकालय, कोचिंग संस्थान, छात्रावास और भोजनालय हैं, जो सैकड़ों विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करते हैं। प्राधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या

पुलिस ने बताया कि अधिकतर पीड़ित छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी थे जिनमें विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) की तैयारी करने वाले भी शामिल थे।

संरचनात्मक खामियां, ऊपरी मंजिलों पर जारी निर्माण गतिविधि या भवन नियमों का उल्लंघन इमारत ढहने की वजह बना। दिल्ली नगर निगम ने मामले में एक सहायक अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता को नियुक्त कर दिया है।

जनवरी-मई का औसत एक्वूआइ आठ वर्षों में सबसे बेहतर रहा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

दिल्ली में पिछले आठ वर्षों में इस साल जनवरी से मई के बीच हवा सबसे साफ दर्ज की गई। हालांकि, इसमें कोविड प्रभावित वर्ष 2020 शामिल नहीं है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्वूएम) ने सोमवार को आंकड़े जारी कर यह जानकारी दी। सीएक्वूएम ने बताया कि इस वर्ष इस अवधि में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्वूआइ) सुधरकर 211 रहा। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर

एक पोस्ट में सीएक्वूएम ने बताया कि वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों के दौरान औसत एक्वूआइ 211 रहा, जबकि 2025 की समान अवधि में यह 214, 2024 में 231, 2023 में 213, 2022 में 238, 2021 में 235, 2019 में 237 और 2018 में 243 था। वहीं, कोविड-19 पूर्णबंदी (लाकडाउन) के कारण वर्ष 2020 में एक्वूआइ सुधरकर 181 पर आ गया था। आयोग ने यह भी कहा कि वर्ष 2020 और 2021 को छोड़कर, इस साल मई में दिल्ली का औसत एक्वूआइ पिछले आठ वर्षों में दर्ज किया गया, दूसरा सबसे बेहतर सूचकांक था। मई 2026 में औसत एक्वूआइ 157 दर्ज किया गया।



शुभारंभ गुरुग्राम में सोमवार को नए आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन लेकर जाते पुलिसकर्मी।

मुखर्जी नगर में एक इमारत में लगी आग, छात्रा झुलसी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक तीन मंजिला इमारत में आग लगने से एक छात्रा झुलस गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिकारी ने बताया कि मुखर्जीनगर के इंदिरा विहार स्थित एक तीन मंजिला इमारत में रविवार की देर रात आग लगी, जिसमें पेंडिंग गेस्ट (पीजी) आवास भी संचालित था। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि आग

इमारत के भूतल में लगी जहां बिजली का सामान रखा हुआ था। आग तेजी से फैली और दूसरी मंजिल तक के हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत में मौजूद सभी लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर आइटीओ इलाके में स्थित स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) परिसर में शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय की दूसरी मंजिल पर सोमवार को आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग की घटना में किसी के भी हाताहत होने की सूचना नहीं है।

योजना

सड़कों की बढ़ेगी चौड़ाई, 72 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेस-वे पर बनेगा गोल चक्कर

जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधा जुड़ेगा न्यू नोएडा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 1 जून।

न्यू नोएडा का भी जेवर के नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सीधा संपर्क होगा। इसके लिए गंगा एक्सप्रेस-वे से 72 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेस प्रस्तावित है। यह लिंक एक्सप्रेस-वे यमुना एक्सप्रेस-वे जोड़ा जाएगा, जो जनपद बुलंदशहर से जाएगा। इसका अधिकांश हिस्सा न्यू नोएडा के गांवों से होकर जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ ने सतीश पाल ने बताया, लिंक एक्सप्रेस-वे पर गोलचक्कर (रोटरी) बनाकर इसे न्यू नोएडा से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को आगामी नोएडा बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इस



गोल चक्कर के बनने से न्यू नोएडा के अधिकांश गांव और प्रस्तावित सेक्टर लिंक एक्सप्रेस-वे आपस में जुड़ जाएंगे। जिसके जरिए जेवर हवाई अड्डे तक पहुंचना आसान होगा। वहीं, नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी क्रांति शेखर ने बताया कि इस्टर्न पेरीफेरल के आसपास जहां सड़क बनी है,

जनगणना में लापरवाही, सात कर्मियों पर गिरी गाज

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 1 जून।

जनगणना-2027 के कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर नोएडा प्राधिकरण ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। लगातार धीमी प्रगति और कर्मचारियों की उदासीनता को देखते हुए दो नियमित कर्मचारियों के निलंबन और पांच संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अन्य विभागों के उन कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है, जिन्होंने अब तक जनगणना कार्य शुरू नहीं किया है। प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश सिंह के मुताबिक जनगणना-2027 का कार्य प्रगति पर है। कुल 2284 हाउस लिस्टिंग ब्लाक

जनगणना कार्य पर जा रहे शिक्षक की हादसे में मौत
थाना दनकोर थाना क्षेत्र के चांगोली मोड़ के पास जनगणना ड्यूटी पर जा रहे शिक्षक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। शरकपुर ग्राम निवासी बालकिशन खुर्जा क्षेत्र के हसनपुर गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। सोमवार को घर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले थे, लेकिन चांगोली मोड़ के पास हादसे का शिकार हो गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक गाड़ी के साथ भाग गया।

(एचएलबी) में से 1172 एचएलबी पर कार्य चल रहा है, जबकि 16 एचएलबी का काम पूरा किया जा चुका है। वहीं, 1096 एचएलबी पर अब तक काम शुरू ही नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महत्त्व के इस कार्य में कई कर्मचारी रुचि

नहीं ले रहे हैं। इसको देखते हुए प्राधिकरण की नियमित कर्मचारी श्रेता तलवार और पिंकी मावी को नियुक्त किया गया है। वहीं, संविदाकर्मी नीरज, ईश्वर तोमर, महबूब अली, राजेश शर्मा और धर्मेन्द्र सिंह की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं।

नोएडा पुस्ता रोड की 12 साल बाद होगी मरम्मत

नोएडा, 1 जून (संवाददाता)।

सेक्टर-94 से सेक्टर-135 तक 11.20 किलोमीटर के यमुना पुस्ता मार्ग की 'री-सर्फेसिंग' और साफ-सफाई के लिए नोएडा प्राधिकरण ने 34.18 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। जिसमें से 11 करोड़ रुपये प्राधिकरण ने सिंचाई विभाग को दे दिए हैं। बताया गया है कि जून में ही पुस्ता मार्ग पर काम शुरू कर दिया जाएगा। चार लेन वाली इस सड़क की 'री सर्फेसिंग' होने से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। यह सड़क 2014 में बनी थी। इसके बाद मरम्मत नहीं होने से पूरी सड़क उखड़ चुकी है। इस पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं और और घनी झड़ियां खड़ी हुई हैं। नोएडा के एसीईओ सतीश पाल ने बताया कि बताया कि पहले सड़क की सफाई करवाई जाएगी।

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

अभिलेखि की अभिव्यक्ति (ईंओआई)

ओएनजीसी अपने मेसरागा एस्टे (पंजीकृत) में नई प्रकल्प (NG) के कच्चे तेल के पूर्व-उत्पन्न एवं निष्क्रीयण के लिए बृहद अखिल अतिरिक्त कुनिन को स्वामित्व/श्रिक्रय पर स्वामित्व करने की इच्छुक है, ताकि रिहायश-उद्देश के तहत की निर्माणाधीन गुप्तता प्राप्त की जा सके (0.2% से कम BSAW तथा 10PTB से कम नामक)। बृहद क्रम में, ओएनजीसी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित, तकनीकी रूप से समतुल्य तथा विशिष्ट रूप से महत्वाकांक्षी/प्रमुख सदस्यों से अभिलेखि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित करती है ऐसे साझेदार, जिन्होंने पूर्व में डीसाइवर तकनीकी की अर्हता की हो - नई गुप्तता NG को तेल का विस्तृत निरक्षण एवं पालन स्तर पर टेक्नोएटोमेटिक डिजाइनिंग प्रक्रिया करने तथा प्रक्रिया की गारंटी, प्रक्रिया डिजाइन और जॉइंट-निवारण सभी प्रमुख रहते। राबसे उपयुक्त डिजाइनिंग तकनीकी की अनुसंधान करें। अधिक जानकारी और जानकारी प्राप्त करना एवं करने के लिए, कृपया यहाँ जाएँ: <https://tenders ONGC.co.in> और <https://ONGCIndia.com>

इसका पूर्ण नाम अमेरिकन पेटेंट नंबर 1, 210 अल्ट्रा-लॉक फ्लो, दूसरी मंजिल, स्यामोय वॉशिंग सेंटर, मसूर विहार फेज-1, दिल्ली-110091, टेलीफोन: +91-120-2328011-20 फ़ैक्स: +91-120-2328010 ईमेल: cs@indiaexpocart.com, वेबसाइट: www.indiaexpomart.com

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

इंडिया एक्सपोसिशन मार्ट लिमिटेड
सोआइएन: U99999DL2001PLC10396

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 1, 210 अल्ट्रा-लॉक फ्लो, दूसरी मंजिल, स्यामोय वॉशिंग सेंटर, मसूर विहार फेज-1, दिल्ली-110091, टेलीफोन: +91-120-2328011-20 फ़ैक्स: +91-120-2328010 ईमेल: cs@indiaexpocart.com, वेबसाइट: www.indiaexpomart.com

शेयरधारकों के हेतु सूचना

15वीं असाधारण सामान्य बैठक का नोटिस और ई-वोटिंग की सूचना

सूचित किया जाता है कि इंडिया एक्सपोसिशन मार्ट लिमिटेड ('कंपनी') के शेयरधारकों की 15वीं असाधारण सामान्य बैठक ('ईवीएम') मंगलवार, 23 जून, 2026 को 11:30 बजे (भारतीय समयानुसार) 'गवर्निंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्डरिंग हाउस बिलिंग सोसाइटी लिमिटेड', कल्याण केंद्र, 9, पश्चिम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057 में आयोजित की जा रही है, ताकि शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से भेजे गए नोटिस में बताए गए व्यवसाय को पुरा किया जा सके।

ईवीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिन्होंने ईमेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत है। इसकी भौतिक प्रतियां अन्य सभी शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.indiaexpomart.com और नेशनल सिन्योरिटीय डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evotingnsdl.com पर उपलब्ध है। ईवीएम की सूचना प्रेषण का काम सोमवार, 1 जून, 2026 को पूरा हो चुका है।

ईवीएम में किए जाने वाले कारोबार से संबंधित दस्तावेज ईवीएम की तारीख तक, शनिवार, रविवार और राजस्थान छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्यदिन 2026 में दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के, और उस पर लागू नियमों के अनुसार और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2, शेयरधारकों को नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर, एनएसडीएल द्वारा सुमतदायक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 20 जून 2026 को सुबह 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार) से शुरू होगी और सोमवार, 22 जून, 2026 को शाम 5:00 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त होगा। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मांफ्रेड को निलंबित कर दिया जाएगा। ई-वोटिंग के निर्देशों के लिए कृपया ईवीएम का नोटिस देखें।

कंपनी ईवीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा भी प्रदान करेगी। ईवीएम में भाग लेने वाले शेयरधारक, जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे ईवीएम में अपने वोट के अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होंगे। जिन शेयरधारकों ने ईवीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने की आवश्यकता नहीं होगी।

रिमोट ई-वोटिंग या ईवीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 16 जून, 2026 है। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग या ईवीएम में उपलब्ध मतदान सुविधा का लाभ उठाएगा का हकदार होगा।

कोई भी व्यक्ति जिसने इस नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया हो या कंपनी का शेयरधारक बना हो अथवा कट ऑफ तारीख पर अंतर किया हो, तो वे भी आईडी/ब्राउज़र आईडी नंबर, का उल्लेख कर evoting@nsdl.com या cs@indiaexpocart.com पर एक अनुरोध भेज कर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

किसी भी सवाल के लिए, आप एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingnsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सामग्रीयक पृष्ठ जाने वाले प्रश्न (एएफएचए) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं। किसी भी शिकायत के मामले में, आप एनएसडीएल से 022-48867000 पर संपर्क कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर पहुंच सकते हैं।

मतदान के परिणाम संबंधित नियमों के तहत निर्धारित अनुसार घोषित किए जाएंगे और उपर्युक्त कंपनी और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी पोस्ट किए जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
इंडिया एक्सपोसिशन मार्ट लिमिटेड के लिए
 एसडी /-
 अनुपम शर्मा
 2 जून, 2026
 दिल्ली
 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

Sarin Housing Finance Ltd.
सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
 कार्यालय पता: प्लॉट नंबर 492, उत्तम विहार, फेज-3
 पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 492, उत्तम विहार, फेज-3
 पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 492, उत्तम विहार, फेज-3, आर्यादा कॉम्प्लेक्स
 कॉम्प्लेक्स, आर्यादा, नई दिल्ली-110033

मांग सूचना

क्र.	कार्यक्रम (सी) / (एस-कॉन्डर (सी)) / (एमएनटी (सी)) के नाम एवं बिना सूचना की सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि तथा समाप्त की तिथि
1.	1. मसूर पुरा मकान (कॉन्डर) 2. 24.03.2026	27-05-2026
2.	कल्याण पुरा मकान (एस-कॉन्डर) दोनों निवासी खानपुर छात्रा, मसूर, उत्तर प्रदेश-281401 3. 23.05.2026 ब्राह्मण खाना संस्था - LAMTR0322-00004590 मांग दिनांक 31.05.2026 तक	(रमपे दो सप्ताह समाप्त होने तक नौ पंचवार मांग) दिनांक 31.05.2026 तक
अपल संचालित का विवरण:- एक प्लॉट, क्षेत्रफल 66.45 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 192 के एक भाग पर स्थित, 107 छ्वाय/परिधि मात्र पर विकसित नई आवासीय, सहसलीय संस्था, जिसे मसूर (एनसी सीएम) एर प्रकर है - पूर्व: 12.5 फीट, 12 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: 12.5 फीट, किरी अन्न प्लांट का प्लॉट, उत्तर: 40 फीट, क्षेत्रफल का प्लॉट, दक्षिण: 40 फीट, विक्रेता का प्लॉट। शीट संख्या: सि. 13.10.2020, पुरान संख्या 01, खंड संख्या 8246, ज़म संख्या 39-70, ज़म संख्या 12263		
2.	1. जीवन्त कुमार पुरा मकान सिंग (कॉन्डर) 2. 25-05-2026 2. यमरा श्री पुरा मकान सिंग (एस-कॉन्डर) दोनों निवासी सायबंद पुरा अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश-281307 मांग दिनांक 31.05.2026 तक 3. LAAGR0523-00007897 मांग दिनांक 31.05.2026 तक	25-05-2026 6. 13.775/- (रमपे एक सप्ताह तहत हज़ार सात सौ पचास मात्र) दिनांक 31.05.2026 तक
अपल संचालित का विवरण:- एक प्लॉट, खसरा संख्या 281 का एक भाग, जिनका मांग 52.89 वर्ग वर्ग अर्थात् 44.32 वर्ग मीटर है। इसकी भूमि का मांग इस प्रकार है - पूर्व: 33 फीट, पश्चिम: 35 फीट, उत्तर: 14 फीट, दक्षिण: 14 फीट। यह मकान दान पुरा, नई आवासीय संस्था, सहसलीय संस्था, जिसे आर्यदा में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं - पूर्व: विनोद कुमार का प्लॉट, पश्चिम: सचिवीय कुमर का प्लॉट, उत्तर: श्रीमती पुनलक्ष्मी सिंह का क्षेत्र, दक्षिण: 6 मीटर चौड़ा पल्ला। पंजीकरण की तिथि: 15.12.2024, पुरान संख्या 03, खंड संख्या 2644, ज़म संख्या 281-296, ज़म संख्या 84-23		
1. मसूर पुरा मकान (कॉन्डर) 2. 20-05-2026 2. दुष्मान पुरा मकान (एस-कॉन्डर) दोनों निवासी मकान नंबर 247, राजका माल, मसूर, उत्तर प्रदेश-201001 मांग दिनांक 30.04.2026 तक 3. LAGZB0121-00002789 मांग दिनांक 30.04.2026 तक	20-05-2026 5. 86,181/- (रमपे पांच सप्ताह समाप्त होने तक नौ पंचवार मांग) दिनांक 30.04.2026 तक	
अपल संचालित का विवरण:- गौदा संस्था 8, मसूर, जिसे एन के अधिकार के (अंतिम एन के अधिकारक मालिक नहीं है), नए/परिष्कार संख्या 63/575 (पुरान नंबर 85, पुरान नंबर 249), जिनका मांग 13.93 वर्ग मीटर अर्थात् 150 वर्ग फीट है। यह संस्था नई कॉन्डर, मसूर, उत्तर प्रदेश-281401, प्लॉट नंबर 150 पर स्थित है। इसका प्लॉट नंबर है - पूर्व: दुष्मान संस्था है - पूर्व: 12.5 फीट, पश्चिम: 12.5 फीट, उत्तर: 40 फीट, क्षेत्रफल का प्लॉट, उत्तर: 40 फीट, क्षेत्रफल का प्लॉट, दक्षिण: 40 फीट, विक्रेता का प्लॉट। शीट संख्या: सि. 13.10.2020, पुरान संख्या 01, खंड संख्या 8246, ज़म संख्या 39-70, ज़म संख्या 12263		
4.	1. जीवन्त कुमार पुरा मकान सिंग (कॉन्डर) 2. 27-05-2026 2. मंगी श्री पुरा मकान (एस-कॉन्डर) 3. 28.83,564/- दोनों निवासी यमरा मकान नंबर 64, मंडली (179), परिष्कार, हरियाणा - 121101 ब्राह्मण खाना संस्था - LALDI0124-00010030 मांग दिनांक 09.06.2026 तक	27-05-2026 3. 28,83,564/- (रमपे अठारह सप्ताह निगमों की दिशा में) दिनांक 09.06.2026 तक
अपल संचालित का विवरण:- प्लॉट संख्या 77, क्षेत्रफल 194.81 वर्ग मीटर (अंतिम 233 वर्ग मीटर), परमाण एवं सहसलीय संस्था, मसूर, उत्तर प्रदेश-281401, प्लॉट नंबर 150 पर स्थित है। इसका प्लॉट नंबर है - पूर्व: 12.5 फीट, पश्चिम: 12.5 फीट, उत्तर: 40 फीट, क्षेत्रफल का प्लॉट, उत्तर: 40 फीट, क्षेत्रफल का प्लॉट, दक्षिण: 40 फीट, विक्रेता का प्लॉट। शीट संख्या: सि. 13.10.2020, पुरान संख्या 01, खंड संख्या 8246, ज़म संख्या 39-70, ज़म संख्या 12263		
5.	1. राम कुमार पुरा मकान सिंग (कॉन्डर) 2. 20-05-2026 2. रेखा श्री अनंद मकान (एस-कॉन्डर) 3. 16,24,298/- 3. युष्मान पुरा मकान (एस-कॉन्डर) सभी निवासी मकान नंबर 52, पहली मंजिल, ब्लाक-बी, फेज-1, विवा विहार, दिल्ली, दिल्ली-110085, ब्राह्मण खाना संस्था - LAGZB0922-00005711 और LAGZB0922-00003481	20-05-2026 16,24,298/- (रमपे दो सप्ताह समाप्त होने तक नौ पंचवार मांग) दिनांक 30.04.2026 तक दिल्ली-110085, ब्राह्मण खाना संस्था - LAGZB0922-00005711 और LAGZB0922-00003481
अपल संचालित का विवरण:- प्लॉट संख्या 377, क्षेत्रफल 194.81 वर्ग मीटर (अंतिम 233 वर्ग मीटर), परमाण एवं सहसलीय संस्था, मसूर, उत्तर प्रदेश-281401, प्लॉट नंबर 150 पर स्थित है। इसका प्लॉट नंबर है - पूर्व: 12.5 फीट, पश्चिम: 12.5 फीट, उत्तर: 40 फीट, क्षेत्रफल का प्लॉट, उत्तर: 40 फीट, क्षेत्रफल का प्लॉट, दक्षिण: 40 फीट, विक्रेता का प्लॉट। शीट संख्या: सि. 13.10.2020, पुरान संख्या 01, खंड संख्या 8246, ज़म संख्या 39-70, ज़म संख्या 12263		
6.	1. हनुमंत पुरा मकान सिंग (कॉन्डर) 2. 21.45,827/- 2. मंगी श्री अनंद मकान (एस-कॉन्डर) दोनों निवासी मंगी कॉन्डर, प्रथम मकान, विवा मकान, उत्तर प्रदेश-202001 मांग दिनांक 09.06.2026 तक 3. LAALG0924-00012235 मांग दिनांक 09.06.2026 तक	21-45,827/- (रमपे इकतीस सप्ताह निगमों की दिशा में) दिनांक 09.06.2026 तक
अपल संचालित का विवरण:- एक आवासीय संचालित जिनका मांग 100 वर्ग मीटर (पूर्व में 83.61 वर्ग मीटर) है, जो खसरा संख्या 294 का एक हिस्सा है। यह मसूर, परमाण एवं सहसलीय संस्था, जिसे आर्यदा में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं - पूर्व: 18 फीट, उत्तर: एक किरी अन्न का मकान, पश्चिम: 18 फीट, उत्तर: एक किरी सड़क, उत्तर: 50 फीट, उत्तर: एक सार्वजनिक का मकान, दक्षिण: 50 फीट, उत्तर: एक हिंसा मकान का मकान। पंजीकरण की तिथि: 04.10.2024, पुरान संख्या 01, खंड संख्या 14278, ज़म संख्या 265-286, ज़म संख्या 13494.		
7.	1. यमरा पुरा मकान सिंग (कॉन्डर), 2. 27-05-2026 2. रेखा श्री अनंद मकान (एस-कॉन्डर), 3. 7,16,995/- मांग दिनांक 09.06.2026 तक 3. युष्मान पुरा मकान (एस-कॉन्डर) सभी निवासी मकान नंबर 52, पहली मंजिल, ब्लाक-बी, फेज-1, विवा विहार, दिल्ली, दिल्ली-110085, ब्राह्मण खाना संस्था - LAGZB0922-00005711 और LAGZB0922-00003481	27-05-2026 7,16,995/- (रमपे सात सप्ताह समाप्त होने तक नौ पंचवार मांग) दिनांक 09.06.2026 तक
अपल संचालित का विवरण:- खसरा संख्या 437 में स्थित एक प्लॉट, जिनका मांग 50 वर्ग मी (पूर्व में 41.30 वर्ग मीटर) है, जो खसरा संख्या 294 का एक हिस्सा है। यह मसूर, परमाण एवं सहसलीय संस्था, जिसे आर्यदा में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं - पूर्व: 12.5 फीट, पश्चिम: 12.5 फीट, उत्तर: 40 फीट, क्षेत्रफल का प्लॉट, उत्तर: 40 फीट, क्षेत्रफल का प्लॉट, दक्षिण: 40 फीट, विक्रेता का प्लॉट। शीट संख्या: सि. 13.10.2020, पुरान संख्या 01, खंड संख्या 8246, ज़म संख्या 39-70, ज़म संख्या 12263		

इसका पूर्ण नाम अमेरिकन पेटेंट नंबर 1, 210 अल्ट्रा-लॉक फ्लो, दूसरी मंजिल, स्यामोय वॉशिंग सेंटर, मसूर विहार फेज-1, दिल्ली-110091, टेलीफोन: +91-120-2328011-20 फ़ैक्स: +91-120-2328010 ईमेल: cs@indiaexpocart.com, वेबसाइट: www.indiaexpomart.com

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएँ: <https://tenders.ongc.co.in>

सार्वजनिक सूचना

सभी संबंधितों को यह नोटिस दिया गया है और आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि कंपनी को प्रस्तावित मेगा वाणिज्यिक विकास विस्तार परियोजना के लिए 21-433/2024-आईए-III दिनांक 27/05/2026 को भारत सरकार के प्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ('एमओईएफ') द्वारा पर्यावरण मंजूरी जारी की गई है। प्लॉट संख्या एलपी-1B-02, गेट वे डिस्ट्रिक्ट, एरोसिटी, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। उक्त प्यावरण मंजूरी की प्रतियां एमओईएफसीसी/एआईएए/परिवेश पोर्टल की वेबसाइट पर उपलब्ध है <https://parivesh.nic.in>।

M/3ANGEL/DEVELOPERS LIMITED
 3rd Floor, Worldmark 2, Asset 8, Aerocity, New Delhi - 110037
 Phone No.: 011-41384000

DFM FOODS LTD.



SABSE BADI DEALS, SABSE BADA FAAYDA!

JOIN INDIA'S MOST TRUSTED

DEALS CHANNEL

SAVE MORE
SPEND LESS!



100% REAL DEALS



LIMITED TIME OFFERS



BEST PRICES GUARANTEED

SAB PE
BADI
BACHAT!

UP TO







90% DISCOUNT DEALS



BIGGEST DISCOUNTS • BEST BRANDS • LIMITED STOCK

LIMITED STOCK

JOIN KARO AUR PAO SABSE BADI LOOT DEALS!

<p>boat Airdopes 141 TWS Earbuds</p>  <p>₹2,990 ₹249</p> <p>92% OFF YOU SAVE ₹2,741</p>	<p>Noise Pulse 2 Smart Watch</p>  <p>₹4,999 ₹349</p> <p>93% OFF YOU SAVE ₹4,650</p>	<p>Apple iPhone 13 128GB</p>  <p>₹59,900 ₹5,399</p> <p>91% OFF YOU SAVE ₹54,501</p>	<p>SAMSUNG 32" HD Smart TV</p>  <p>₹25,800 ₹2,800</p> <p>89% OFF YOU SAVE ₹25,800</p>	<p>realme Narzo N55 (6GB+128GB)</p>  <p>₹13,999 ₹799</p> <p>94% OFF YOU SAVE ₹13,200</p>
<p>ASUS Vivobook 15 (i3 12th Gen, 8GB/512GB SSD)</p>  <p>₹40,491 ₹4,049</p> <p>90% OFF YOU SAVE ₹40,491</p>	<p>GREEN SOUL Office Chair Ergonomic</p>  <p>₹14,999 ₹1,499</p> <p>92% OFF YOU SAVE ₹17,500</p>	<p>SAMSUNG 980 500GB NVMe SSD</p>  <p>₹6,999 ₹699</p> <p>91% OFF YOU SAVE ₹6,400</p>	<p>WILDCRAFT Backpack</p>  <p>₹1,850 ₹149</p> <p>93% OFF YOU SAVE ₹1,850</p>	<p>PHILIPS Trimmer Series 3000</p>  <p>₹1,796 ₹199</p> <p>90% OFF YOU SAVE ₹1,796</p>
<p>AGARO Air Fryer 4.5L</p>  <p>₹6,999 ₹699</p> <p>90% OFF YOU SAVE ₹6,300</p>	<p>PUMA Men's Running Shoes</p>  <p>₹3,999 ₹399</p> <p>91% OFF YOU SAVE ₹3,650</p>	<p>ZEBRONICS Study Headphones with Mic</p>  <p>₹1,499 ₹169</p> <p>89% OFF YOU SAVE ₹1,330</p>	<p>PORTABLE Laptop Table Foldable</p>  <p>₹1,299 ₹129</p> <p>90% OFF YOU SAVE ₹1,170</p>	<p>boat Stone 650 Bluetooth Speaker</p>  <p>₹3,999 ₹199</p> <p>95% OFF YOU SAVE ₹3,800</p>



UPTO 90% OFF ON TOP BRANDS



PRICE DROP ALERTS BE THE FIRST TO KNOW



100% GENUINE PRODUCTS



FAST DELIVERY ACROSS INDIA



DEALS ITNI BADI, KI CHOOK GAYE TO PACHTAOGE!



ABHI JOIN KARO AUR LOOTNA SHURU KARO!



JOIN OUR WHATSAPP CHANNEL

- Instant Deal Alerts
- Exclusive Offers
- Limited Stock Updates

CLICK HERE



JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL

- Latest Deals & Offers
- Price Drops Alerts
- Limited Time Offers

CLICK HERE



SAVE TIME SHOP SMART



SAVE MONEY LIVE BETTER



SMART CHOICES. BRIGHTER FUTURE!

SHOP SMART. SAVE BIG. SHINE BRIGHT.



JOIN 1 LAKH+ SMART SHOPPERS & SAVE THOUSANDS EVERY MONTH!

बदलाव के बजाय

पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद हिंसक घटनाएं सामान्य हो चुकी हैं। मगर हाल ही में जब विधानसभा चुनावों के बाद व्यापक फेरबदल हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, तो इसे राज्य में एक बड़े बदलाव का उदाहरण बताया गया। वहां की जनता के बीच एक उम्मीद पैदा हुई कि अगर सत्ता में बदलाव आया है, तो संभवतः इसका असर सरकार के कामकाज से लेकर जमीनी स्तर पर आम लोगों के जीवन पर भी पड़े। मगर पहली बार भाजपा की सरकार बनने के बाद जो हालात दिख रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वहां अराजक तत्त्वों को खुली छूट मिली हुई है, विपक्ष के नेताओं पर सीधे हमले हो रहे हैं और शासन उदासीन है। ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें एक तरह से बदले की भावना से विपक्षी दलों के नेताओं या उनके समर्थकों पर हमले हुए हैं और कानून-व्यवस्था लाचार है। इससे यह सवाल उठा है कि क्या राज्य के लोगों ने इसी तरह के हालात के लिए बदलाव के पक्ष में वोट दिया था। गौरतलब है कि पिछले दो दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दो नेताओं, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर लोगों की भीड़ ने पुलिस या सुरक्षा बलों की मौजूदगी में घातक हमला किया।

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने सोनारपुर दक्षिण पहुंचे थे। मगर आरोप के मुताबिक वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी करते हुए उनके साथ मारपीट की। एक अन्य घटना में तृणमूल कांग्रेस के एक और सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला किया गया। गनीमत रही कि दोनों को किसी तरह भीड़ से निकाल लिया गया। मगर उन पर जिस तरह हमला किया गया, वह सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि लोकतंत्र की बहाली के जिस नारे के साथ चुनावों में जनता का समर्थन मांगा गया, सरकार बदलने के बाद अब वही लोकतंत्र वाधित होता दिख रहा है और राज्य सरकार अराजक तत्त्वों पर काबू पाने के बजाय सब कुछ अपने आप ठीक होने की उम्मीद कर रही है।

सवाल है कि चुनावी नतीजों के बाद राज्य में विपक्षी दलों के समर्थकों या कार्यकर्ताओं के सामने जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, उनके नेताओं की गतिविधियों को जिस तरीके से बाधित किया जा रहा है, उसे किस कसौटी पर लोकतंत्र कहा जाएगा। हिंसक तो समूचे राज्य में कहीं भी प्रतिद्वंद्विता की वजह से अडिस्क या एक दूसरे पर हमले की घटनाओं को पूरी तरह रोकने और किसी भी पार्टी का समर्थन करने वाले अराजक तत्त्वों के खिलाफ सख्ती बरतने के लिए पुलिस को स्पष्ट निर्देश देने की जरूरत है। फिर विपक्षी दलों के नेता अगर लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए जनता के बीच जाते हैं, तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का दायित्व है। पश्चिम बंगाल में चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब राज्य में 'बदला नहीं, बदलाव' और 'भय नहीं, भविष्य' की बात होनी चाहिए। यों भी, अगर नई सरकार ने बदलाव का सपना दिखाया है, तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी राज्य में हर स्तर पर लोकतांत्रिक माहौल को बहाल करना होना चाहिए। राज्य में कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर अगर ऐसे हालात रहे कि विपक्ष को दबाने वाले तत्त्वों को खुली छूट दी गई, तो यह एक तरह से राज्य सरकार की सबसे बड़ी नाकामी होगी।

लापरवाही की कीमत

दिल्ली में साकेत के पास एक इलाके में शनिवार को पांच मंजिला इमारत ढह जाने से पांच विद्यार्थियों सहित छह लोगों की मौत की खबर ने फिर यही साबित किया है कि सरकारी तंत्र के भीतर किस हद तक लापरवाही और गैरजिम्मेदारी का आलम फैला हुआ है। इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए। बचाव अभियान में चौदह लोगों को बाहर निकाला गया। इस हादसे से सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब यह हादसा हुआ, उस समय इमारत की ऊपरी मंजिल पर निर्माण कार्य किसकी अनुमति से हो रहा था। नियमों का उल्लंघन कर इसकी मंजूरी किस स्तर पर दी गई? हालांकि नगर निगम के दो अभियंताओं को निर्लंबित कर दिया गया है। इतने बड़े हादसे पर यह कार्रवाई बहुत छोटी है। कायदे से उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन पर उस भवन के निर्माण और नक्शे की मंजूरी देने का जिम्मा था। मजिस्ट्रेट के स्तर पर जांच के बाद संबंधित अधिकारियों को छानबीन के घेरे में लाया जाना चाहिए।

मगर वास्तव में यह प्रशासन और नगर निकाय की लापरवाही का एक और ज्वलंत उदाहरण है। सवाल है कि इमारत जर्जर हो गई थी, तो संबंधित विभाग ने समय रहते इसे खाली क्यों नहीं कराया। अगर यह प्राथमिक कदम उठा लिया गया होता, तो एक बड़ा हादसा टल सकता था। कोई भी इमारत एक दिन में अचानक नहीं गिरती। उसमें संरचनात्मक कमजोरी धीरे-धीरे सामने आ रही होती है। साकेत में जो इमारत ढह गई, समय रहते उसके मालिक और नगर निगम के अभियंताओं ने सजगता क्यों नहीं बरती और निर्माण मानकों का उल्लंघन क्यों होने दिया गया। उस इमारत में अवैध निर्माण किए जाते रहे और अधिकारी आंखें मूंदे रहे, तो दरअसल यह आपराधिक लापरवाही है। साकेत में हुई घटना पूरी दिल्ली के लिए सबक होनी चाहिए। यहां कई व्यावसायिक और रिहाइशी इमारतें हैं जो भवन निर्माण की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। पिछले दो-तीन दशकों में राजधानी में भवनों के निर्माण का जिस तरह व्यावसायीकरण हुआ है, उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। जर्जर होती कोई इमारत कब ढह जाए, कहां नहीं जा सकता। अवैध और जर्जर इमारतों का पूरी दिल्ली में सर्वे और निरीक्षण होना चाहिए, ताकि समय रहते नागरिकों की जान बच सके।

महंगी शिक्षा के बीच गुम होते सपने



रंजना मिश्रा

कि सी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन उसका मध्यवर्ग होता है। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और प्रगतिशील देश में मध्यवर्ग केवल करदाता या उपभोक्ता भर नहीं है, बल्कि समाज का वह सबसे जागरूक तथा संवेदनशील वर्ग है जो देश के उज्ज्वल भविष्य के सबसे ज्यादा सपने पालता है। एक आम मध्यवर्गीय नागरिक अपने जीवन में अनगिनत संघर्ष करता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी आने वाली पीढ़ी होती है। यह निराशाजनक ही है कि तेजी से बदलते भारत में, यही मध्यवर्ग जटिल दौराह पर खड़ा है, जहां एक ओर उसके पास अपने बच्चों के सुनहरे कल के लिए बुने गए अनगिनत सपने हैं, तो दूसरी ओर उन सपनों को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधनों का गहरा अकाल है। भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना की सबसे मजबूत रीढ़ माने जाने वाले इस वर्ग के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना बन गई है। यह विडंबना ही है कि जिस शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत आधार और अज्ञानता को मिटाने वाला प्रकाश माना जाता था, वह आज विशुद्ध मुनाफे पर आधारित उद्योग में तब्दील हो चुकी है।

आज एक औसत मध्यवर्गीय परिवार की सीमित मासिक आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा निजी स्कूलों की तिजोरियों में जा रहा है। इस बेतहाशा खर्च ने परिवार का पूरा आर्थिक और मानसिक संतुलन चरमरा दिया है। जमीनी हकीकत यही है कि आय और शिक्षा के खर्च के बीच निरंतर बढ़ता अंतर अब केवल एक आर्थिक समस्या नहीं रह गया, बल्कि यह एक ऐसी गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक त्रासदी का रूप लेता जा रहा है, जो दीमक की तरह चुपचाप हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को निगल रही है। निजी स्कूलों की फीस का ढांचा जटिल, भ्रामक और अपारदर्शी हो चुका है। बात अब केवल ट्यूशन फीस तक सीमित नहीं रह गई है। इसके साथ जुड़े कई अन्य शुल्क अभिभावकों की कमर तोड़ रहे हैं। निजी स्कूलों की मुनाफे वाली गतिविधियां केवल भारी-भरकम फीस की रसीद थमाने तक ही नहीं रुकी हैं। यह पूरी व्यवस्था अब बेहद संगठित तरीके से अभिभावकों का शोषण कर रही है। आज स्कूल प्रबंधन ही यह तय करता है कि बच्चों की किताबों किस विशिष्ट प्रकाशक की होंगी और वे शहर की किस दुकान से खरीदी जाएंगी। हर साल पाठ्यक्रम में मामूली फेरबदल कर या प्रकाशक बदल कर पुरानी किताबों के इस्तेमाल की संभावना को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। स्कूल की बर्धियां, विशेष प्रकार के जूते-मोजे, स्कूल बैग और यहां तक कि मामूली स्टेशनरी भी तय दुकान से बाजार मूल्य से कई गुना ऊंचे दामों पर खरीदने का दबाव बनाया जाता है। अभिभावकों के पास न तो सवाल पूछने का अधिकार है, न मोलभाव करने की गुंजाइश और न ही किसी अन्य विकल्प को चुनने की स्वतंत्रता।

जब शिक्षा वास्तविक ज्ञान और अच्छे संस्कार देने के बजाय विशुद्ध रूप से उत्पाद बन जाती है, तो बच्चों के भीतर छिपी स्वाभाविक रचनात्मकता, मौलिकता



और जिज्ञासा नष्ट होने लगती है। उनकी जगह एक बेलगाम प्रतियस्पर्धा, बिना समझे रटने की प्रवृत्ति और हर समय दूसरों से आगे निकलने का भारी दबाव घर कर लेता है। आजकल के बच्चे छोटी उम्र में ही यह समझने लगते हैं कि उनकी शिक्षा के लिए उनके माता-पिता किस हद तक आर्थिक और मानसिक कष्ट झेल रहे

मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों का भविष्य आज उनकी प्रतिभा या कठिन परिश्रम पर उतना निर्भर नहीं है, जितना इस बात पर निर्भर हो गया है कि उनके माता-पिता की आर्थिक हैसियत क्या है। यह पूरी स्थिति हमारे समाज में एक बहुत ही खतरनाक और चौड़ी खाई पैदा कर रही है। एक तरफ समाज का वह छोटा-सा, लेकिन ताकतवर आधिजात्य वर्ग है और दूसरी तरफ देश का वह विशाल मध्यवर्ग है, जिसके प्रतिभाशाली बच्चों का दम उचित संसाधनों और धन की वजह से घुट रहा है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पच्चीस फीसद आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन व्यवहार में इस पर अमल में जिस तरह की अड़चनें दिखती रही हैं, उसमें इससे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती।

ऐसे में अपनी स्वाभाविक रुचि के विषयों को चुनने के बजाय वे उन डिग्रियों की तरफ भागने को मजबूर हो जाते हैं जो उन्हें जल्द से जल्द नौकरी का अवसर

देते हों। इस तरह हमारा देश भविष्य के कई महान वैज्ञानिकों, विचारकों और नवोन्मेषकों को इसलिए खो रहा है, क्योंकि शिक्षा की लागत ने उनके सपनों के खुले आसमान को एक छोटे से आर्थिक पिंजरे में तब्दील कर दिया है। मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों का भविष्य आज उनकी प्रतिभा या कठिन परिश्रम पर उतना निर्भर नहीं है, जितना इस बात पर निर्भर हो गया है कि उनके माता-पिता की आर्थिक हैसियत क्या है। यह पूरी स्थिति हमारे समाज में बहुत ही खतरनाक और चौड़ी खाई पैदा कर रही है। एक तरफ समाज का वह छोटा-सा, लेकिन ताकतवर आधिजात्य वर्ग है, जिसके बच्चों के पास उच्च स्तर की शैक्षिक सुविधा उपलब्ध है और दूसरी तरफ देश का वह विशाल मध्यवर्ग है, जिसके प्रतिभाशाली बच्चों का दम उचित संसाधनों और धन की वजह से घुट रहा है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पच्चीस फीसद आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन व्यवहार में इस पर अमल में जिस तरह की अड़चनें दिखती रही हैं, उसमें इससे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती।

इस पूरी त्रासदी का एक सबसे निराशाजनक पहलू हमारे सरकारी स्कूलों की बदहाली और उनकी खस्ताहाल व्यवस्था है। अगर आजादी के इतने दशकों बाद भी हमारी सरकारी स्कूल शिक्षा के उच्च मानकों को कायम कर पाने में सफल रहतीं, तो बहुत सारे भारतीय परिवार निजी स्कूलों के तंत्र की मनमानी का शिकार नहीं होते। सरकारी शिक्षा व्यवस्था की निरंतर विफलता, योग्य शिक्षकों की भारी कमी, बुनियादी ढांचे का अभाव और प्रशासनिक जवाबदेही की शून्यता ने ही निजी स्कूलों के लिए एक ऐसा बाजार तैयार कर दिया है, जिसमें उन्हें मनमानी करने की छूट मिली हुई है। आज मध्यवर्ग के पास कोई दूसरा मजबूत विकल्प बचा ही नहीं है। वह जानता है कि यदि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा जाएगा, तो वहां की व्यवस्था में उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसी डर के कारण लोग अपनी हैसियत से बाहर जाकर और कर्ज लेकर भी निजी स्कूलों का रुख करने के लिए तैयार रहते हैं। एक समय था जब लोग केवल उच्च शिक्षा या मेडिकल-इंजीनियरिंग की महंगी पढ़ाई के लिए बैंकों से कर्ज लेते थे, लेकिन आज स्थिति यह आ गई है कि स्कूलों की शिक्षा पूरी करवाने के लिए भी कई लोगों को कर्ज लेना पड़ रहा है।

अब समय आ गया है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर पारदर्शी और दूरदर्शी राष्ट्रीय नीति विकसित की जाए और उसे पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए। यह सुनिश्चित करना राज्य और सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि शिक्षा मानकमाना मुनाफा कमाने वाला व्यवसाय न बने। शिक्षण संस्थानों को बिना किसी लाभ के सख्तान करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। इसके समांतर, इस पूरी समस्या का सबसे प्रभावी और एकमात्र स्थायी समाधान यही है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली यानी सरकारी स्कूलों का युद्धस्तर पर कायाकल्प किया जाए। जब तक हमारे देश के हर शहर, कस्बे और हर गांव के सरकारी विद्यालय निजी स्कूलों को शिक्षा की गुणवत्ता में कड़ी टक्कर नहीं देंगे, तब तक भारत का मध्यवर्ग निजी स्कूलों के इस मकड़जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा।

उदारता का सौंदर्य

गिरीश पंकज

समाज में न जाने कितने ऐसे लोग हैं, जो गहन अध्ययन करने के बाद अनेक मामलों में विशेषज्ञ की तरह हो जाते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, जो ज्ञान का अतिरिक्त होने पर दंभ के शिकार भी हो जाते हैं। वे अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। ऐसे लोग कुछ कम पढ़े-लिखे लोगों को हीन दृष्टि से देखने लगते हैं। मगर यह भी सच है कि ऐसे लोग धीरे-धीरे समाज से कटते जाते हैं और अपने दंभ की दुनिया में लीन रहकर ही खुश रहते हैं। जबकि हमारे यहां कहा गया है कि फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, उदार हो जाते हैं। किसी अज्ञानी माने जाने वाले व्यक्ति से भी वे बड़े प्रेम से मिलते हैं। ठीक वही तरीका, जैसे किसी बच्चे से बड़े लोग प्रेम से बातियाते हैं और उसकी नावानी को अनदेखी करके उसके साथ खेलते हैं। इससे यह भी संभव है कि अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की राह पकड़ लें।

यों भी हर व्यक्ति ज्ञानी या महाज्ञानी नहीं हो सकता। इसी तरह हर कोई प्रखर अध्ययनशील नहीं हो सकता... हर कोई हर क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता।

तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह उपेक्षा का पात्र है। वह भी इसी समाज का अंग है। उसने भी मेहनत की, मगर चाँछित सफलता नहीं मिल सकी। इसलिए उसके साथ भी प्रेमपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं, जो अपनी धार्मिकता को लेकर बड़े ही आक्रामक होते हैं। वे हर जगह अपनी धार्मिकता का ढोल पीटते नजर आते हैं और कहते हैं कि मैं तो इतने उपवास करता हूँ... इतने घंटे पूजा-अर्चना करता हूँ। मगर सच यह है कि उनके आचरण में उनके पूजा-पाठ का कोई अंश नजर नहीं आता। वे हर घड़ी कटुता से भरे रहते हैं। उनके मुंह से प्रेम के बोल नहीं फूटते। कभी-कभी तो ऐसे लोग गलियां भी देते दिखते हैं। इस तरह के कुछ लोग भले ही खुद को सात्विक बताते हों, सादे वस्त्रों में रहते हों, लेकिन उनके आचरण में वह सात्विकता नजर नहीं आती, जो किसी धार्मिक व्यक्ति में सहज ही होनी चाहिए।

धार्मिकता अगर मनुष्य को बेहतर और ज्यादा मानवीय न बनाए, तो वह बेकार है। ज्ञान अगर मनुष्य को विनम्र न बनाए, सहिष्णु न बनाए, उदार न बनाए, तो ऐसा ज्ञान किस काम का? केवल किताबों में दर्ज बातों को याद कर लेना ज्ञान नहीं होता। ऐसा ज्ञान रटने वाले को तोता की तरह कहा जाएगा। तोता जो सुनता है, वही दोहराने लगता है। फिर चाहे भजन हो या अपशब्द, लेकिन जो व्यक्ति विवेकशील है, वह जो ग्रहण करता है, उसके

अनुरूप आचरण भी करता है। इसीलिए यह तोते से अलग होता है। अगर कोई अध्ययनशील ज्ञानी व्यक्ति अपने व्यवहार में कटु है, अभद्र है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह सही मायने में सच्चा ज्ञानी नहीं है। उसके पास केवल किताबी ज्ञान है। उसे अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। जिसे आत्मज्ञान हो चुका है, वह विनम्र होगा। उदार होगा। वह सबकी बातें ध्यान से सुनेगा। वह किसी को अतिरिक्त होने पर दंभ के शिकार भी हो सकता है। समस्या यह है कि चाहे ज्ञान का मामला हो या धन-दौलत का, आमतौर पर जिसके पास अधिक मात्रा में होता है, वह अपने आप को विशिष्ट समझने लगता है। धनी व्यक्ति निर्धन व्यक्ति को देखकर घुरी बना लेता है। वह किसी की आर्थिक मदद नहीं करना चाहता, जबकि उसके पास जो धन आया है, वह इसी समाज से अर्जित है। लेकिन वह यह बात समझ नहीं पाता और कृपण बना रहता है। मगर जो व्यक्ति उदार होकर अपने धन को सामाजिक कार्यों में खर्च करता है, तो उससे उसकी प्रतिष्ठा ही बढ़ती है। लोग उसे आदर के साथ देखते हैं। बुला कर उसका सम्मान भी करते हैं। मगर जो व्यक्ति विशुद्ध रूप से धनपशु बना रहता है, वह एक दिन खा-पीकर मर जाता है, तब भी सब उसकी निंदा ही करते हैं।

समाज में हमेशा दानी या उदार व्यक्ति को महत्व मिलता है। फिर चाहे वह ज्ञान दान करे, चाहे धन दान करे, चाहे श्रमदान करे। दशरथ मांझी जैसे लोग श्रमदान करके अमरता को प्राप्त कर जाते हैं। उदारता, विनम्रता, सहिष्णुता- ये तमाम गुण बेहतर मनुष्य के लक्षण होते हैं। जिनमें ऐसे लक्षण नहीं होते, उनकी राह अलग हो जाती है। कई बार वे अपराध के मार्ग भी पर चल पड़ते हैं। अपराध सिर्फ हत्या,बलात्कार या चोरी-डकैती ही नहीं है, किसी का दिल दुखाना भी अपराध है। किसी को अपने से छोटा समझना अपराध है। किसी सज्जन का उपहास उड़ाना भी अपराध है। किसी अच्छे व्यक्ति की उपेक्षा करना अपराध है। किसी को कम जान है, यह समझ कर उसे हेय दृष्टि से देखना अपराध है।

अगर कोई ज्ञानी है, तो अपने ज्ञान को उदारता के साथ सबको बांटते रहना चाहिए। अधिक जान है, तो उसे भी उदारता के साथ बांटना चाहिए। अक्सर ऐसा होता नहीं है। जो लोग ऐसा नहीं करते, वे अपनी सीमित दुनिया में मगन रहते हैं, लेकिन जब कभी एकांत में आत्ममंथन करते हैं कि क्या खोया, क्या पाया की सूक्ति पर विचार करते हैं, तब पता चलता है कि उन्होंने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन खोया उससे भी कहीं ज्यादा। मगर जो ज्ञानीजन होते हैं, वे कुछ नहीं खोते, बल्कि निरंतर पाते ही रहते हैं। यह पाना ही उनकी वास्तविक कमाई है। असल पूंजी है। इसका सुख वही व्यक्ति उठा सकता है, जो निर्मल मन वाला है, उदार है और समरसताजीवी है।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

छीजता भरोसा

नी

एक प्रश्नपत्रों को वायुसेना की निगरानी में वितरित किए जाने का निर्णय केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि भारतीय परीक्षा प्रणाली पर गहराते अविश्वास का प्रतीक भी है। क्या देश की शिक्षा व्यवस्था और उससे जुड़ी एजिसियों इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि अब उन्हें सेना की मदद लेनी पड़ रही है? क्या शिक्षा माफिया इतने संगठित और प्रभावशाली हो चुके हैं कि सामान्य प्रशासनिक तंत्र उन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा? राष्ट्रीय परीक्षा एजिसियों का मूल दायित्व निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा कराना है। मगर जब प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं सामने आती हैं, तब यह धारणा मजबूत होती है कि कहीं न कहीं तंत्र कमजोर पड़ा है। यदि एक संगठित गिरोह परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र हासिल कर लेता है, तो यह केवल बाहरी अपराध नहीं माना जा सकता। वायुसेना की निगरानी में प्रश्नपत्र बांटना बीमारी का समाधान नहीं है। सरकार हमेशा सेना के साथ में परीक्षाएँ नहीं करा सकती। एनटीए का पूरी तरह पुनर्गठन होना चाहिए। शीर्ष अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय होनी चाहिए, ताकि चूक होने पर केवल जांच कमेटी न बैठे, बल्कि त्वरित और अनुकरणीय कार्रवाई हो।

- युगल किशोर राही, छपरा

भटकती दिशा

‘न

शे का जाल’ (संपादकीय, 28 मई) पढ़ कर गहरी चिंता हुई। आज नशीले पदार्थों का फैलाव कारोबार केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि समाज और युवाओं के भविष्य पर गंभीर खतरा बन चुका है। शहरों से लेकर गांवों तक नशे का जाल जिस तेजी से फैल रहा है, वह बेहद भयावह स्थिति को दर्शाता है। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर भारी मात्रा में कोकीन की बरामदगी यह साबित करती है कि तस्करो के हीसले लगातार बढ़ रहे हैं। बार-बार इतनी बड़ी

सवाल का पटाक्षेप

‘शु

चित्ता की खातिर’ (संपादकीय, 28 मई) पढ़ा। विहार से शुरू हुई मतवाला सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर विवाद का दायरा पश्चिम बंगाल तक पहुंचा। कई सवाल उठाए गए। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद अंततः इस मामले का पटापेक्ष हुआ। अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण को न केवल वैध करार दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए ऐसा किया जाना

जेब पर असर

सामाजिक क्षेत्र को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में चार बार बढ़ाती कर आम जन को कमर तोड़ दी है। मूल्य वृद्धि का सीधा असर यातायात साधनों, बाजार और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। अधिजात्य वर्ग और नीति निर्माताओं का बाजार से सीधा कोई सरोकार नहीं होता। मगर निम्न मध्य और मध्यवर्गीय परिवारों पर असर पड़ता है। महंगाई बढ़ना तब नहीं अखरता, जब आय के साधनों और खर्चों के बीच समन्वय हो। गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि के साथ डीजल और पेट्रोल के दामों में बार-बार वृद्धि होने से आम आदमी के सामने संकट खड़ा हो गया है। जबकि केंद्र और राज्य की सरकारें जनहित में इस महंगाई से निजात दिला सकती थीं। महंगाई का विरोध करने वाले कुछ दलों के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकारों भी अधिक कर वसूल रही हैं।

- सुधाकर आशावादी, ब्रह्मपुरी, मेरठ

संवाद

जनसत्ता | 2 जून, 2026



आस्था

प्रयागराज में ज्येष्ठ सोमवार के अवसर पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गंगाजल ले जाते श्रद्धालु।

बोल

ईरान समुद्र समझौता करना चाहता है और यह अमेरिका एवं हमारे साथ खड़े देशों के लिए अच्छा समझौता होगा। बस निश्चित रहिए, अंत में सब ठीक हो जाएगा - हमेशा ऐसा ही होता है।
- डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति



बोल

हिज्बुल्लाह की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने और हमारे नागरिकों पर हमलों के कारण इजराइली सेना को बेरुत के दक्षिणी उपनगर वहीये में हमले का आदेश दिया है। - बैंगामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री



सम-सामयिक

ईरान और अमेरिका में किन किन मुद्दों पर फंसा है पेच

जनसत्ता संवाद

ईरान और अमेरिका के बीच गतिरोध जारी है। दोनों देशों में प्रस्तावों और जवाबी प्रस्तावों का आदान-प्रदान चल रहा है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। पांच बड़े मुद्दे सामने आए हैं, जो ईरान और अमेरिका के बीच असहमति की मुख्य वजह बने हुए हैं। इनमें यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम, ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार का भविष्य, होमजु जलमार्ग पर नियंत्रण, क्षेत्र में ईरान समर्थित समूहों की गतिविधियां और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम शामिल हैं।

दरअसल, अमेरिका की 14 सूत्री योजना में यूरेनियम संवर्धन रोकना, 60 फीसद संवर्धित यूरेनियम के ईरानी भंडार को खत्म करना या पूरी तरह सीमित करना और होमजु को बिना शर्त खोलना शामिल है। इस योजना में 30 दिन की एक अवधि भी शामिल है, ताकि दूसरे मुद्दों पर बातचीत का रास्ता तैयार किया जा सके। इनमें क्षेत्र में ईरान समर्थित समूह और उसका मिसाइल कार्यक्रम शामिल हैं। ईरान इन प्रस्तावों को स्वीकार करने को ऐसी जंग में आत्मसमर्पण के बराबर मानता है। ईरान रियायतें हासिल करने की कोशिश कर रहा है और अपने जवाब में तत्काल युद्धविराम, सभी प्रतिबंध हटाने, हज्जा देने, होमजु पर अपनी संप्रभुता को मान्यता देने और परमाणु वार्ता बाद में करने की मांग कर रहा है। ईरान ने यह भी कहा है कि वह अपने कुछ संवर्धित यूरेनियम को कम स्तर पर लाने या किसी तीसरे देश को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन उसने पूरा भंडार सौंपने से इनकार किया है।

पहला मुद्दा यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का है। ईरान और अमेरिका के बीच यह सबसे अहम और पुराना विवादित मुद्दा है। अमेरिका के नजरिये से यह इस सवाल से जुड़ा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता से कितनी दूरी पर है। प्राकृतिक यूरेनियम अकेले बहुत प्रभावी नहीं होता। संवर्धन प्रक्रिया यूरेनियम के ऊर्जावान हिस्से यानी आइसोटोप 235 को मात्रा बढ़ाती है, ताकि इसे ऐसे ईंधन में बदला जा सके जिसका इस्तेमाल परमाणु संयंत्रों में हो सके। जैसे-जैसे यूरेनियम का संवर्धन अनुपात बढ़ता है, उसके सैन्य इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ता जाता है। ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के तहत ऊर्जा उत्पादन, रिसर्च और मेडिकल जरूरतों जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार पर जोर देता है। दूसरी तरफ, अमेरिका और इजराइल इस कार्यक्रम को परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश का बहाना मानते हैं। आमतौर पर तीन से पांच फीसद संवर्धन स्तर बिजली संयंत्रों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि 20 फीसद संवर्धित यूरेनियम शोध के मकसद से इस्तेमाल किया जाता है। इससे ऊपर का संवर्धन परमाणु हथियार के लिए यूरेनियम के इस्तेमाल का रास्ता खोल देता है। पिछली गर्मियों की 12 दिन की जंग तक ईरान 60 फीसद संवर्धन स्तर तक पहुंच चुका था। इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने दावा किया था कि तेहरान ने हजारों उन्नत सेंट्रीफ्यूज लगाए हैं और बड़ा भंडार जमा कर लिया था।

नतांज, फोर्दे और इस्फहान के संयंत्रों पर हमलों के बाद संवर्धन गतिविधियां लगाभ रुक गईं और कई उपकरण बर्बाद हो गए। अमेरिका ने लंबे समय तक ईरान में संवर्धन पूरी तरह रोकने की मांग की है। दूसरी तरफ, ईरान शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अस्थायी प्रतिबंध, कम संवर्धन स्तर और अंतरराष्ट्रीय निगरानी स्वीकार करने को तैयार दिखता है, लेकिन कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करने या गतिविधियों को विदेश भेजने को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानते हुए खारिज करता है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2024 की तुलना में 2025 में ऐसे मामलों की संख्या काफी बढ़ी। रूस के सशस्त्र बलों को भी पहली बार

नियामक संघर्षों में यौन हिंसा के मामलों को दर्ज करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार इजराइली और रूसी बलों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी बंदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया है। 35 पन्नों की इस रिपोर्ट में 12 देशों के 77 सरकारी और गैर-सरकारी पक्षों को काली सूची में शामिल किया गया है, जिन पर संघर्ष के दौरान यौन हिंसा में शामिल होने या उसके लिए जिम्मेदार होने का संदेह है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2024 की तुलना में 2025 में ऐसे मामलों की संख्या काफी बढ़ी। रूस के सशस्त्र बलों को भी पहली बार

नियामक संघर्षों में यौन हिंसा के मामलों को दर्ज करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार इजराइली और रूसी बलों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी बंदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया है। 35 पन्नों की इस रिपोर्ट में 12 देशों के 77 सरकारी और गैर-सरकारी पक्षों को काली सूची में शामिल किया गया है, जिन पर संघर्ष के दौरान यौन हिंसा में शामिल होने या उसके लिए जिम्मेदार होने का संदेह है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2024 की तुलना में 2025 में ऐसे मामलों की संख्या काफी बढ़ी। रूस के सशस्त्र बलों को भी पहली बार



जानें-समझें

क्वाड : नई दिल्ली सम्मेलन

ताकतवर देशों संग संतुलन की इबारत

जनसत्ता संवाद

हाल में नई दिल्ली में हुए क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया) शिखर सम्मेलन में जो सहमतियां बनी हैं, उनके दूरगामी कूटनीतिक नतीजे निकलने की संभावना जताई जा रही है। वैश्विक स्तर पर अशांति के दौर में इस सम्मेलन को कूटनीतिक तालमेल की परीक्षा माना गया। नई दिल्ली की बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर जो सहमति बनी, उससे चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति पर लगातार कसने में मदद मिलेगी। इसके लिए चारों देश रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत करेंगे।

नई शुरुआत

इस बैठक ने एक तरह से क्वाड की वापसी की शुरुआत की, क्योंकि पिछले दशक के शुरुआत में चीन के सवाल पर चारों देशों की भू-राजनीतिक मजबूरियों और रणनीतिक दृष्टिकोण में मतभेदों से यह समूह बिखर गया था। वर्ष 2017 के बाद से, क्वाड ने संवाद के लिए प्राथमिक मंच के रूप में विदेश मंत्री स्तर पर बैठकें की हैं, जिससे मार्च 2021 में आभासी स्तर पर आयोजित पहले नेता-स्तरीय शिखर सम्मेलन का रास्ता खुला। वर्ष 2021 से 2023 के बीच दो बार क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, लेकिन 2025 में नई दिल्ली में होने वाला सम्मेलन विफल रहने से यह गति थम गई थी।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सक्रियता

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की व्यस्तताओं पर नजर डालने से पता चलता है कि तनाव और अनिश्चितताओं के बावजूद, क्वाड के भीतर अभियानों में बहुत कम परिचालन व्यवधान आया है। क्वाड साल भर सक्रिय रहा है, जिसमें अमेरिका के पास आयोजित मालाबार अभ्यास भी शामिल है। हाल ही में, अंतर-संचालनीयता और युद्ध की तैयारियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए अमेरिका-फिलीपींस बाल्टिक अभ्यास ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर वाशिंगटन के परिचालन फोकस के लचीलेपन को साबित किया है। अमेरिका में 2025 में लिए गए फैसलों से क्वाड पर असर दिखा। इनमें प्रमुख रहा शुल्क का मामला, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड भागीदारों सहित कई देशों पर अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया।



(फाइल फोटो)



क्वाड की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि वह क्षेत्रीय दिक्कतों को कितनी जल्दी समझता है और चारों देश मिलकर कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि यह समूह सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस पहलू पर ध्यान देना होगा।
- अजय बिसारिया, पूर्व राजनयिक



क्वाड ने समुद्र की निगरानी करने, आपदा के समय लोगों की मदद करने और आपस में साजो-सामान का तालमेल बढ़ाने जैसे जरूरी कामों में अच्छी तरकीबी की है। क्वाड को व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए सार्थक बनाना होगा।
- मीरा शंकर, अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत

बड़े बदलाव

इस समय हिंद-प्रशांत इलाके में बड़े बदलाव हो रहे हैं। अमेरिका मध्य पूर्व की लड़ाइयों में फंसा हुआ है। इस वजह से सुरक्षा के सवाल पर सब परेशान हैं। इस इलाके के ज्यादातर देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा करते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका अपना हाथ पीछे खींचता है, तो वहां खाली जगह बन जाएगी। इस स्थिति का आकलन कर चीन अपना दबाव और सेना बढ़ा रहा है। बाकी देश नए दोस्त और संगठन तो बना रहे हैं, पर अमेरिका जितनी ताकत किसी में नहीं है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक सुदृढ़ सुरक्षा संरचना प्रदान करने के लिए पूरी तरह से वाशिंगटन पर निर्भर रहना अब उन देशों के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं रह गया है, जो इस क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने में रुचि रखते हैं।

चीन सागर का मुद्दा

क्वाड ने जो साझा घोषणापत्र पारित किया, उसमें पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई। कहा गया है, 'हम क्षेत्र में शांति और स्थिरता को खतरों में डालने वाली किसी भी अस्थिरता पैदा करने वाली या एकरतफा कार्रवाई, जिसमें बल या दबाव द्वारा की गई कार्रवाई भी शामिल है, का कड़ा विरोध दोहराते हैं। हम खतरनाक और दबावपूर्ण कार्रवाइयों के संबंध में चिंता व्यक्त करते हैं, जिनमें संसाधन विकास में हस्तक्षेप, नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता में बाधा-बाधा डालना, सैन्य विमानों और तटरक्षक एवं समुद्री मिलिशिया जहाजों द्वारा खतरनाक युद्धाभ्यास, विशेष रूप से जल तोपों और फ्लेयर्स का असुरक्षित उपयोग, और दक्षिण चीन सागर में टक्कर मारना या अवरोध पैदा करना शामिल है।'

शोध

देश के 63 शहरों में बदला बारिश का स्वरूप

जनसत्ता संवाद

तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ-साथ मौसम भी लगातार बदलता जा रहा है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआईटी) हैदराबाद और यूनिवर्सिटी आफ कोलोराडो के वैज्ञानिकों ने अहम अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि पिछले 120 वर्षों में भारत के 63 बड़े शहरों में बारिश के स्वरूप (पैटर्न) में बड़े और अलग-अलग बदलाव आए हैं। यह अध्ययन 1901 से 2022 तक के रोजमर्रा के बारिश के आंकड़ों पर आधारित है। कुछ शहरों में भारी बारिश अचानक बढ़ गई है, जबकि कुछ जगहों पर कुल बारिश कम होती जा रही है।

भारतीय शहरों में बारिश के बदलाव एक जैसे नहीं हैं। उन्हें चार अलग-अलग प्रकार के स्वरूप (पैटर्न) मिले हैं। कुछ शहरों में अचानक और तेज बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कुछ शहरों में सालाना और मानसून की बारिश में लगातार गिरावट देखी गई है, जिससे पानी की कमी और सूखे की स्थिति बन सकती है। इसका मतलब यह है कि एक ही क्षेत्र के पास-पास के शहरों में भी मौसम का असर अलग-अलग तरीके से हो रहा है।

'अर्बन क्लाइमेट' नामक पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि सबसे बड़े बदलाव 1950 के दशक से 1970 के दशक के बीच हुए थे। इसी समय बारिश के पैटर्न में अचानक बदलाव देखने को मिला। उदाहरण के लिए, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के कई शहरों में मानसून की बारिश में कमी आई है। इससे वहां पानी की उपलब्धता पर असर पड़ा है। दूसरी ओर, बंगलुरु जैसे शहरों में हाल के वर्षों में बहुत तेज और भारी बारिश की घटनाएं बढ़ी हैं।

आइआईटी हैदराबाद और यूनिवर्सिटी आफ कोलोराडो के अध्ययन में पता चला है कि 120 वर्षों के दौरान भारत के 63 शहरों की बारिश का स्वरूप बदल गया है। कहीं अचानक बाढ़, कहीं सूखा, जलवायु में बदलाव का खतरा बढ़ गया है। कुछ शहरों में अत्यधिक भारी बारिश बढ़ी, जिससे शहरी बाढ़ का खतरा तेजी से और गंभीर रूप से बढ़ा है। कई तटीय शहरों में मानसून और सालाना बारिश में गिरावट दर्ज हुई, जिससे जल संकट और सूखे की आशंका बढ़ गई है।



(फाइल फोटो)

स्थायी मौसम पर भी पड़ सकता है, जिसे पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है। यह अध्ययन शहरी योजनाकारों के लिए एक अहम संकेत देता है कि अब मौसम को स्थिर मानकर योजना नहीं बनाई जा सकती। शहरों को खुद को बदलना होगा। कहीं पर जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना होगा, तो कहीं पानी बचाने की नीतियों को बढ़ाना होगा।



विश्व परिक्रमा

युद्ध और यौन हिंसा : इजराइली व रूसी बल काली सूची में

जनसत्ता संवाद

दुनिया भर के संघर्षों में यौन हिंसा के मामलों को दर्ज करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार इजराइली और रूसी बलों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी बंदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया है। 35 पन्नों की इस रिपोर्ट में 12 देशों के 77 सरकारी और गैर-सरकारी पक्षों को काली सूची में शामिल किया गया है, जिन पर संघर्ष के दौरान यौन हिंसा में शामिल होने या उसके लिए जिम्मेदार होने का संदेह है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2024 की तुलना में 2025 में ऐसे मामलों की संख्या काफी बढ़ी। रूस के सशस्त्र बलों को भी पहली बार



सूची में शामिल किया गया है। उन पर यूक्रेन युद्ध के दौरान युद्धबंदियों और असैन्य बंदियों के साथ यौन हिंसा करने के आरोप लगे हैं। वर्ष 2025 की सूची में इजराइल की सेना और

सुरक्षा बलों के साथ-साथ हमला के लड़ाके भी शामिल हैं। हमला के पहले ही सात अक्टूबर 2023 के हमले के बाद काली सूची में डाला जा चुका था।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंTONियो गुतेर्रेस ने पिछले वर्ष रूस एवं इजराइल को चेतावनी दी थी कि उन्हें सूची में डाला जा सकता है। इजराइल और रूस के राजदूतों ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और गुतेर्रेस की आलोचना की। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और फिलिस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्रों में बंद फलस्तीनियों के खिलाफ यौन हिंसा के एक जैसे कई मामले दर्ज किए। इसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साथ यौन हिंसा, सामूहिक बलात्कार, जबरन नाम करने और बलात्कार की धमकियां जैसे मामलों का उल्लेख है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया।



व्यक्तित्व

ईशा : निशानेबाजी में रचा इतिहास, विश्व रिकार्ड के साथ जीता सोना

जनसत्ता संवाद

भारत की युवा निशानेबाज ईशा सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में देश की शान बढ़ा दी। 21 साल की ईशा ने 'आइएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026' में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकार्ड बना डाला। फाइनल में ईशा ने 50 में से 43 सटीक निशाने लगाए और उन्होंने सीनियर एवं जूनियर दोनों श्रेणियों का विश्व रिकार्ड अपने नाम कर लिया। म्यूनिख में खेले गए फाइनल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन यांग जी-इन भी मौजूद थीं। वहां ईशा ने जिस आत्मविश्वास और निरंतरता के साथ निशाने लगाए, उसके सामने बाकी सभी निशानेबाज फीके पड़ गए।

ईशा सिंह ने फाइनल की शुरुआत ही धमाकेदार अंदाज में की। उन्होंने लगातार तीन सटीक निशानों की सीरीज लगाई और शुरुआत से ही मुकामले पर पकड़ बना ली। 'एलिमिनेशन राउंड' में जहां बड़े-बड़े नाम दबाव में चूकते दिखे, वहीं ईशा मजबूत दिखीं। हर राउंड के साथ उनका आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। आखिर में उनका स्कोर 43 हिट्स तक पहुंचा, जो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अब नया विश्व रिकार्ड है। इस प्रदर्शन ने उन्हें सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं दिलाया, बल्कि सीधे 'आइएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल' के लिए भी क्वालिफाई करा दिया, जो इस साल रोम में खेला जाएगा।

ईशा का यह प्रदर्शन इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में पांचवें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। असली धमाका उन्होंने फाइनल में किया, जहां उनका खेल पूरी तरह अलग स्तर पर पहुंच गया। ओलंपिक में सोना जीतने वाली यांग जी-इन ने क्वालिफिकेशन में शानदार स्कोर बनाया था और उन्हें खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। लेकिन फाइनल में वह अपनी लय बरकरार नहीं रख सकीं और पांचवें स्थान पर खिसक गईं। ईशा की इस ऐतिहासिक जीत ने पुरे भारत को गर्व महसूस कराया। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी उनके प्रदर्शन से प्रभावित नजर आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर ईशा की जमकर तारीफ की।

ईशा के पदक से भारत ने टूर्नामेंट में 10 ओलंपिक स्पर्धाओं में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य पदक हासिल किए। भारत कुल मिलाकर तीन स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य पदकों के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि चीन 10 स्वर्ण पदकों के साथ पहले और कोरिया छह स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

ईशा का यह इस साल का तीसरा व्यक्तिगत आइएसएसएफ पदक था। इससे पहले उन्होंने विश्व कप चरण में स्वर्ण और रजत पदक जीता था। अब वे दिसंबर में दोहा में आइएसएसएफ विश्व कप फाइनल में हिस्सा लेंगी।



जेईई एडवांस्ड 2026 के परिणाम घोषित : लड़कियों में अरोही देशपांडे शीर्ष पर रहीं

शुभम कुमार मेधा सूची में अब्बल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (एडवांस्ड) 2026 के नतीजे सोमवार को घोषित हुए, जिसमें दिल्ली जेन के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक हासिल करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया जबकि लड़कियों में अरोही देशपांडे ने बाजी मारी। जेईई (एडवांस्ड) 2026 में कुल 56,880 अभ्यर्थी सफल हुए, जिनमें 10,107 छात्राएं और 46,773 छात्र शामिल हैं। जेईई (एडवांस्ड) देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और अन्य प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए मुख्य परीक्षा है।

परीक्षा में शामिल हुआ अकेला 'थर्ड जेंडर' छात्र सफल नहीं हो सका। दिव्यांग श्रेणी में 3,052 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 2,864 ने दोनों पेपर दिए और 887 सफल रहे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली जेन के शुभम कुमार ने कामन रैंक लिस्ट (सीआरएल) में 360 में से 330 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त



शुभम कुमार

आरोही देशपांडे।

किया। इसी जेन की अरोही देशपांडे शीर्ष रैंक हासिल करने वाली छात्रा बनीं। उन्होंने 360 में से 280 अंक प्राप्त करके पूरे देश में 77वीं रैंक हासिल की।

कबीर छिल्लर ने 329 अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि जतिन चाहर 319 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। शीर्ष स्थान

पर रहे शुभम कुमार ने कहा कि मैं दो वर्ष से जेईई एडवांस्ड की तैयारी कर रहा था और मुझे उम्मीद थी कि मेरी मेहनत अच्छी रैंक दिलाएगी।

अब जब मैंने पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है तो बहुत खुशी हो रही है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की द्वारा जारी परिणाम आंकड़ों के अनुसार 1,87,389

पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 1,79,694 अभ्यर्थियों ने 17 मई को आयोजित जेईई (एडवांस्ड) 2026 के दोनों पेपर दिए। जोनवार परिणामों में आईआईटी मद्रास जोन से सर्वाधिक 14,294 अभ्यर्थी सफल हुए, इसके बाद आईआईटी बांबे से 12,389 और आईआईटी दिल्ली से 10,697 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की।

सफल विद्यार्थी 'जोसा 2026 काउंसिलिंग' के लिए पंजीकरण करें : आईआईटी रुड़की

आईआईटी रुड़की ने सभी जेईई एडवांस्ड पात्रता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों से काउंसिलिंग प्रक्रिया में पंजीकृत होने को कहा है। संस्थान के अनुसार, जो अभ्यर्थी परीक्षा में सफल रहे हैं, वे कक्षा 12 की परीक्षा में आए अंकों या प्रतिशत की परवाह किए बिना 'जोसा 2026 काउंसिलिंग' प्रक्रिया के लिए पंजीकरण जरूर करें। इससे उन हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है जो बोर्ड परीक्षा के अंकों की वजह से अपनी पात्रता को लेकर असमंजस में थे। अब ऐसे सभी विद्यार्थी काउंसिलिंग के शुरुआती दौर का हिस्सा बनकर अपनी दावेदारी पेश कर सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, संख्या बढ़कर 37

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और इसी के साथ शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी। यह संख्या बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या 38 से एक कम है।

केंद्रीय विधि मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा सोमवार सुबह जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की

वरिष्ठ अधिवक्ता वैकिता सुब्रमण्यम मोहना, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, पंजाब एवं

हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनके शपथ लेने और पदभार ग्रहण करने के बाद उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या औपचारिक रूप से 37 हो जाएगी।

सरकार ने पिछले महीने एक कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया था जिसके तहत प्रधान न्यायाधीश सहित शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई। न्यायालय में पहले से ही दो पद खाली थे। स्वीकृत संख्या बढ़ाए जाने के बाद शीर्ष अदालत में कुल पद रिक्त छह हो गए थे। उच्चतम न्यायालय में सोमवार को पांच नियुक्तियों के बाद एक पद रिक्त रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने 27 मई को इन पांच नामों की सिफारिश की थी और चार दिन के भीतर नियुक्तियां कर दी गईं।

पेज 1 का बाकी

'भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा'

संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक वार्ता की। आंग ह्लाईंग पांच दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि म्यांमा भारत की 'नेबरहुड फ्रेंड' (पड़ोसी पहले), 'एक्ट ईस्ट' और 'महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति) नीतियों के संगम पर स्थित है।

चर्चाओं में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के महत्त्व पर जोर दिया गया, जिसमें व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहायता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं। दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर चल रही चर्चाओं का संज्ञान लिया और उनके शीघ्र निष्कर्ष की उम्मीद जताई। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि बेहतर संपर्क से इस क्षेत्र में आपसी लाभ वाले आर्थिक संबंध और साझा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इस संबंध में, दोनों पक्षों ने कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग

को पूरा करने की दिशा में मिलकर काम करने के महत्त्व पर सहमति जताई।

म्यांमा में संसदीय चुनावों के बाद राष्ट्रपति बनने के दो महीने से भी कम समय में वह भारत यात्रा पर आए हैं। सप्ताहारी सैन्य जुटा के खिलाफ वर्षों से जारी विरोध प्रदर्शनों के बाद ये चुनाव दिसंबर और जनवरी में कराए गए। सैन्य जुटा ने एक फरवरी, 2021 को तख्तापलट कर आंग सान सू ची की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बेदखल कर दिया था।

सूची के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यात्रा पर आए राष्ट्रपति के साथ इस मुद्दे को उठाया और चर्चा मुख्य रूप से म्यांमा में जारी शांति प्रक्रिया के संदर्भ में हुई थी। इस मुद्दे पर भारत के निरंतर रुख को स्पष्ट करते हुए विदेश सचिव ने कहा कि भारत स्थायी शांति, समावेशिता और सभी हितधारकों को बातचीत की मेज पर लाने की आवश्यकता का समर्थन करता रहा है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तय

विश्वास जताया कि इन मुद्दों के सुलझने के बाद दोनों देश बीटीए के पहले चरण को अंतिम रूप देकर जल्द ही उस पर हस्ताक्षर करेंगे। वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के मुख्य वातांकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं, जबकि भारतीय टीम की कमान वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन के हाथों में है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, बचे हुए मुद्दों पर पूरी स्पष्टता आने के बाद अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर भारतीय वाणिज्य मंत्री से मुलाकात कर

सकते हैं। इस बातचीत में अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 301 के तहत लगाए गए शुल्क और इसके अंतर्गत चल रही जांच पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है।

दरअसल, अमेरिका की धारा 301 के तहत चल रही इस जांच के दायरे में भारत और चीन सहित दुनिया की लगभग 60 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। गोयल ने कहा कि पहला चरण संपन्न होने के बाद एक अधिक व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में आगे की बातचीत शुरू की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

कंप्यूटर से नहीं होगी नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2026 पुनः परीक्षा कंप्यूटर के जरिए आयोजित कराने संबंधी याचिका को स्वीकार करने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) पहले से ही कई समस्याओं का सामना कर रही है।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने राजद सांसद सुधाकर सिंह और अन्य की याचिका को 27 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए नीट-यूजी को मौजूदा कलम-कागज पद्धति के बजाय

नीट पुनर्परीक्षा को साफ-सुथरे तरीके से कराया जाए : संसदीय समिति

संसद की एक स्थायी समिति ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि 21 जून को 'नीट-स्नातक' की पुनर्परीक्षा पारदर्शी और साफ-सुथरे तरीके से हो। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और शिक्षा मंत्रालय के कुछ अन्य अधिकारी शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडिकटा प्रवेश परीक्षा 'नीट-स्नातक' की 21 जून को फिर से होने वाली परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन यदि यह होता है तो फिर उनका इस्तीफा मांगा जाएगा।

कंप्यूटर के जरिए आयोजित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। एनटीए ने 12 मई को, प्रश्न पत्र लीक से जुड़े आरोपों के बीच मंडिकल

तमिलनाडु : भाजपा छोड़ेंगे अन्नामलाई

सोमवार को कहा कि आगामी दो दिन में वह अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। अन्नामलाई ने दिल्ली रवाना होने से पहले चेन्नई हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान नई राजनीतिक पार्टी बनाने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि 'वह दो दिनों में जवाब देंगे और अपना रुख स्पष्ट करेंगे'।

चर्चाओं से परिचित एक शीर्ष सूत्र ने बताया, 'वे आईपीएस से इस्तीफा देने के बाद भाजपा द्वारा दिए गए अवसरों, अनुभवों और राजनीतिक सफर के लिए नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं।' यदि मंगलवार को इस घटनाक्रम की औपचारिक रूप से पुष्टि हो जाती है, तो यह अभिनेता से राजनेता बनें सी जोसेफ विजय की चुनावी जीत के बाद से तमिलनाडु में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलावों में से एक होगा, जिससे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को पुनर्व्यवस्थित किया और लगभग हर प्रमुख राजनीतिक दल के भीतर नए सवाल खड़े कर

दिए। कई हफ्तों से अन्नामलाई के भविष्य को लेकर अटकलें चेन्नई और दिल्ली दोनों जगह राजनीतिक चर्चाओं का मुख्य विषय बनी हुई थीं। हालांकि अफवाहें बढ़ती ही जा रही थीं, लेकिन अन्नामलाई ने आमतौर पर ऐसी अटकलों को शांत करने के लिए दिए जाने वाले स्पष्ट खंडन से परहेज किया।

भाजपा के अंदरूनी हलकों में, चर्चा धीरे-धीरे इस बात से हटकर कि अन्नामलाई नाखुश थे या नहीं, इस बात पर केंद्रित हो गई कि वास्तव में वह क्या चाहते थे। पार्टी के आंतरिक मामलों से परिचित कई नेताओं ने बताया कि अन्नामलाई ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को जो संदेश दिया था, वह संक्षेप में दो विकल्पों तक सीमित हो गया था: या तो उन्हें उस पद पर बहाल किया जाए जहां वे कम से कम सात वर्षों के लिए दीर्घकालिक स्वायत्तता और अधिकार के साथ तमिलनाडु में भाजपा का नेतृत्व कर सकें, या उन्हें एक अलग राजनीतिक मार्ग अपनाने की अनुमति दी जाए।

दिन भर नहीं चला सीबीएसई का पुनर्मूल्यांकन पोर्टल

आधिकारिक पोर्टल पर लगातार 'रखरखाव के अधीन' संदेश प्रदर्शित होता रहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने की घोषित तिथि बाद भी सोमवार को दिन भर पोर्टल नहीं खुला। सीबीएसई के आधिकारिक पोर्टल पर लगातार 'रखरखाव के अधीन' संदेश प्रदर्शित होता रहा। इससे हजारों विद्यार्थी हलकान रहे। वे इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रतीक्षारत रहे।

सीबीएसई सूत्रों ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल जल्द चालू होने की उम्मीद है। पोर्टल को विद्यार्थियों के लिए सक्रिय करने से पहले तकनीकी और भुगतान संबंधी कार्य पूरे किए जा रहे हैं। सीबीएसई ने यह कहते हुए कि वह विद्यार्थियों के लिए एक सुचारु और जटिरहित



12वीं कक्षा के जो भी विद्यार्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्कैन कार्डों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अनुभव सुनिश्चित करना चाहता है। पहले पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। सूत्रों के अनुसार, बोर्ड वर्तमान में आवेदकों के लिए पोर्टल खोलने से पहले सिरस्टम को तकनीकी रूप से जटिरहित बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अधिकारियों द्वारा पोर्टल की

महाराष्ट्र : 'लाडकी बहिन' योजना से 80 लाख महिलाएं बाहर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना के लिए आनलाइन माध्यम से केवाईसी की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद 80 लाख महिलाएं इस योजना से बाहर हो गई हैं। इस लेंकर विपक्षी दलों ने तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार 'गंभीर वित्तीय संकट' के कारण लाभार्थियों को योजना से बाहर कर रही है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि हालांकि, 30 अप्रैल की 'ई-केवाईसी' समयसीमा के बाद लाभार्थियों की संख्या 2.4 करोड़ से घटकर करीब 1.7 करोड़ रह गई है, लेकिन यह कटौती केवल 'ई-केवाईसी' न कराने के कारण नहीं, बल्कि पात्रता मानदंडों का पालन न करने से भी जुड़ी है। सरकार ने लाभार्थियों को ई-केवाईसी पूरी करने के लिए आठ महीने का समय दिया था।

करीब 50 से 55 लाख महिलाओं ने यह प्रक्रिया पूरी ही नहीं की, जबकि दो से तीन लाख ने इस दौरान अपनी जूटियां सुधारीं। इसके अलावा, करीब 12 लाख महिलाएं आयकर दाता

विपक्ष ने लगाया 'वित्तीय संकट' का आरोप

पाई गई, जो 2.5 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा से अधिक हैं और 4.5 लाख से अधिक महिलाएं 65 वर्ष की अधिकतम आय सीमा पार कर चुकी थीं। करीब पांच लाख महिलाएं पहले से नमो शेतकरी योजना का लाभ उठा रही हैं।

'ई-केवाईसी' पूरी करने के बावजूद मासिक किस्त न मिलने की शिकायतों पर अधिकारी ने कहा कि वास्तविक लाभार्थियों की अंतिम संख्या एक सप्ताह में स्पष्ट हो जाएगी और शिकायतों का पुनः सत्यापन किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी खारिज किया कि 80 लाख महिलाओं को केवल 'ई-केवाईसी' न कराने के आधार पर योजना से हटाया गया है। वहीं, विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद गुट) नेता जयंत पाटिल ने दावा किया कि योजना से लाभार्थियों को हटाना राज्य के 'गंभीर वित्तीय संकट' को दर्शाता है।

पाटिल ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के 'गंभीर वित्तीय संकट' को दावा और विधानसभा चुनावों से पहले इस योजना को लागू किया गया था जिसके तहत महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक सहायता दी जाती है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा

सावधान, सीबीएसई में जेबकतरे बैठे हैं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 'आन-स्क्रीन मार्किंग' (ओएसएम) प्रणाली को लेकर दावा किया कि आज छात्र को अपनी ही उत्तर पुस्तिका की सही जांच के लिए 2000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। आरोप लगाया है कि सीबीएसई में जेबकतरे बैठे हैं, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। सोमवार को राहुल गांधी ने 'एक्स' पर लिखा कि जेबकतरों से सावधान, आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। उन्होंने पूछा कि सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आए तो आपकों क्या मिलता है?

राहुल गांधी ने कहा कि एक बिल है, इसमें प्रति विषय डिजिटल स्कैन कापी का खर्च 100

कांग्रेस का आरोप जानबूझकर कमजोर की थी निविदा प्रक्रिया

मीडिया और प्रचार के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मप्र प्रधान के इस्तीफे तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस ने सवाल किया कि शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में 36 बड़ी कमियों की चेतावनी दिए जाने के बावजूद, सीबीएसई ने इसे छात्रों पर क्यों थोपा? कोएम्ट कंपनी को ठेका देने से पहले टेडर की शर्तों, स्कैन गुणवत्ता और साइबर सुरक्षा मानकों में ढील देने का आदेश किसने दिया था? उन्होंने बताया कि आन-स्क्रीन मार्किंग के लिए टेकेदार दूढ़ने से पहले सीबीएसई को तीन अलग-अलग निविदा जारी करनी पड़ी, पहले निविदा में कोई बोली नहीं लगी और दूसरे में तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाला नहीं मिला।

रुपए, फिर से कुल करने का खर्च प्रति पेपर 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन का खर्च प्रति प्रश्न 25 रुपए है। उन्होंने कहा कि अपनी ही उत्तर पुस्तिका की सही जांच के लिए एक बच्चे को 2000 रुपए तक भरने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि

सोचिए, जब चार लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डाले हैं तो सीबीएसई कितनी कमाई कर रहा है। जब स्कैनिंग फोन से हुई हो, गलत मार्किंग तय है और उसे ठीक करवाने की कीमत बच्चा भर रहा है।

भाजपा की बैठक में राज्यसभा और विधानसभा चुनावों पर चर्चा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्यसभा और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों पर आगे की रणनीतिक तैयारी में जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर राज्य इकाइयों के अध्यक्षों के साथ 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव और मिशन 2027 को लेकर मंथन किया। दस राज्यों में राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने वाले हैं।

राज्यवार का भाजपा कोर ग्रुप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा इन चुनावों के साथ-साथ विधान परिषदों में होने वाले आगामी

चुनावों के मद्देनजर काफी अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राज्य इकाइयों के अध्यक्षों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की इस पर बातचीत हुई।

भाजपा प्रवक्ता संवित पात्रा ने बताया कि बैठक में केंद्र सरकार के संघ, सुरासन और गरीब कल्याण के 12 वर्षों, संगठन के विस्तार, जमीनी स्तर पर पार्टी को और अधिक सशक्त बनाने तथा समाज के विभिन्न वर्गों तक संगठन की पहुंच को व्यापक करने के उद्देश्य से भविष्य की पहलों पर हुई अहम चर्चाओं के बारे में बताया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाजपा की राज्य-स्तरीय गतिविधियों के आकलन के अलावा, वरिष्ठ नेताओं से संगठन के विस्तार से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

बंगाल : 35 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

कोलकाता, 1 जून (भाषा)।

भाजपा विधायक स्वप्न दासगुप्ता, तापस राय और शंकर घोष उन 35 विधायकों में शामिल हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में शुभेदु अधिकारी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के विस्तार के तहत सोमवार को मंत्री पद की शपथ ली। विभागों का बंटवारा मंगलवार को किया जाएगा। राज्य में पहली भाजपा सरकार की विस्तारित मंत्रिपरिषद में भौगोलिक, जातीय और लैंगिक आधार पर सावधानीपूर्वक संतुलन स्थापित किया गया है।

राज्यपाल आरएन बंगाल मंत्रिमंडल विस्तार, विभागों का बंटवारा आज।

रवि ने यहां लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 35 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शुभेदु अधिकारी, मंत्रिमंडल के मौजूदा सदस्य और राज्य प्रशासन के वरिष्ठ नौकरशाह उपस्थित थे। भाजपा के 13 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि तीन को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 19 अन्य को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया।

कैबिनेट मंत्री तापस राय ने बताया कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में होगा। मुख्यमंत्री के अलावा पांच कैबिनेट मंत्रियों ने नौ मई को शपथ ली थी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या वर्तमान में 41 है, जो 294 सदस्यीय राज्य विधानसभा में संविधान द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा 44 से तीन कम है। मंत्रिपरिषद के सदस्य बंगाल के समाज के विभिन्न वर्गों से हैं। भाजपा ने विधाननगर सीट जीतने वाले कैंसर रोग विशेषज्ञ शरदवत मुखर्जी और खरदाहा के प्रोफेसर कल्याण चक्रवर्ती को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया है।

मेरठ : 3600 रुपए के लिए की थी कबड्डी खिलाड़ी की हत्या

मेरठ, 1 जून (जनसत्ता)।

मेरठ में महज 3600 रुपए उधार की रकम को लेकर हुई कहासुनी में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने डेढ़ महीने बाद हत्या का खुलासा किया है। आरोपी की निशानदेही पर रोहता रोड स्थित नाले से शव बरामद किया गया, जो लंबे समय तक पानी और कीचड़ में पड़े रहने के कारण लगभग कंकाल में बदल चुका था। पहचान की अंतिम पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा।

एसएसपी अविनाश पांडे ने सोमवार को बताया कि 17 वर्षीय अनुष्का पाल की हत्या अप्रैल में कर दी गई थी। पुलिस ने फास्ट फूड का ठेला लगाने वाले श्याम धानक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने रुपए मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद अनुष्का के सिर पर डेढ़ से हमला किया और शव को नाले में फेंककर फरार हो गया। पुलिस के

अनुसार, दौराणा क्षेत्र के चिरौड़ी गांव की रहने वाली अनुष्का राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी थीं। पढ़ाई और खेल अभ्यास में सुविधा के लिए वह मेरठ के शोभापुर क्षेत्र में किराए पर रह रही थीं। परिवार को आखिरी

पुलिस ने डेढ़ महीने बाद हत्या का खुलासा किया है।

बार उसने बताया था कि वह प्रतियोगिता में भाग लेने गई है। इसके बाद 16 अप्रैल से उसका मोबाइल बंद हो गया। काफी तलाश के बाद 28 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और काल डिटेल रिकार्ड खंगाले। इनमें अनुष्का की आखिरी लोकेशन आरोपी श्याम धानक के साथ मिली। पूछताछ में चंडीगढ़ से गिरफ्तार आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। परिजनों का आरोप है कि जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगा है उससे पहले भी पूछताछ हुई थी लेकिन उसे छोड़ दिया गया था। पुलिस जांच में सामने आया है आरोपी पर पहले भी एक महिला की हत्या का मामला दर्ज था और वह जमानत पर बाहर था।

पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने

रेल राज्यमंत्री बिट्टू को चार जून को तलब किया

चंडीगढ़, 1 जून (ब्यूरो)।

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कथित जातिसूचक टिप्पणी के मामले में चार जून को पेश होने के लिए सोमवार को समन जारी किया। आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया कि केंद्रीय रेल राज्यमंत्री बिट्टू ने हाल में धूरी में दौरे के दौरान कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस मामले में संगरूर के वरिष्ठ पुलिस

केंद्रीय रेल राज्यमंत्री बिट्टू ने हाल में धूरी में दौरे के दौरान कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था।

अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई लेकिन आयोग ने पुलिस को ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट से असंतोष जाहिर किया है। बिट्टू ने रविवार को अनुसूचित जाति समुदाय से आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगी व स्वीकार किया कि एक मंत्री के रूप में उन्हें ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। वह पंजाब राज्य अनुसूचित

जाति आयोग के समक्ष माफी मांगने को तैयार हैं। यह मामला 26 मई की उस घटना से जुड़ा है जब बिट्टू ने धूरी में भाजपा नेता आंकार सिंह को रिहा करने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बहस की थी। आंकार सिंह को नगर निकाय चुनावों के लिए प्रचार अवधि खत्म होने के दौरान प्रचार करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था। रवनीत सिंह बिट्टू पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा है। दरअसल, 26 मई की घटना का एक वीडियो प्रसारित हो गया था।

भारत, ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू

ओमान में भारत के 98.08% निर्यात पर व भारत में ओमान के 77.79% निर्यात पर शून्य शुल्क

नई दिल्ली, 1 जून (ब्यूरो)।

भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता सोमवार से लागू हो गया। इसके तहत वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न और आभूषण समेत भारत के 98.08 फीसद निर्यात को ओमान के बाजार में बगैर शुल्क प्रवेश और पेशेवरों को आवागमन की बेहतर सुविधा का लाभ होगा। दूसरी तरफ भारत को ओमान से सस्ते खजूर मिलेंगे क्योंकि समझौते के तहत कोटा-आधारित शुल्क रियायतें लागू होंगी। ईरान संकट के बीच इस समझौता के लागू होने से होर्मुज जलमार्ग के प्रभावित रहने पर भी भारत को राहत मिलने की उम्मीद है।

ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीडीपीए) का लागू होना इसलिए भी अहम है, क्योंकि अमेरिकी-ईरान युद्ध की वजह से



गोयल ने कहा कि कृषि और रत्न एवं आभूषण उत्पादों की लगभग 10 खेप तरजीही दरों के तहत खाड़ी देश को भेजी गई।

भारतीय निर्यातकों को खाड़ी देशों में माल भेजने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छह खाड़ी देश ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। भारत ने कुल 12,556 टैरिफ लाइन में से 77.79 फीसद पर शुल्क रियायतें दी हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ लाइन का मतलब किसी वस्तु या उत्पाद के उस विशिष्ट वर्गीकरण कोड से होता है, जिस पर कोई विशेष आयात कर लगाया जाता है।

ओमान के साथ समझौता रणनीतिक : जीटीआरआई

नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

भारत के लिए ओमान के साथ व्यापार समझौता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मस्कट का अधिकतर तट होर्मुज जलमार्ग के बाहर स्थित है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष, व्यवधान या भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौरान भी ओमान भारत के लिए एक भरोसेमंद व्यापार और ऊर्जा मार्ग बना रह सकता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के अनुसार, इस ढिंसे से यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा में निवेश भी है।

जीएसटी संग्रह मई में 1.94 लाख करोड़ रुपए के पार

नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मई में 3.2 फीसद बढ़कर 1.94 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा।

यह वृद्धि वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में सुधार तथा आयात से मिलने वाले कर संग्रह में लगातार बढ़ोतरी के कारण हुई। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई। मई, 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 1.88 लाख करोड़ रुपए रहा था। घरेलू लेनदेन से मई के दौरान केंद्रीय

जीएसटी (सीजीएसटी) संग्रह 37,397 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 45,143 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी (आइजीएसटी) 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि में कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति में 26.9 फीसद की वृद्धि हुई, जो घरेलू मांग को दर्शाती है। वहीं, सेवाओं के क्षेत्र में यह वृद्धि 22.2 फीसद रही जो घरेलू खपत की मजबूती को दिखाती है। आयात से आइजीएसटी संग्रह 19.1 फीसद बढ़कर मई में 59,654 करोड़ रुपए हो गया जो औद्योगिक क्षमता के विस्तार का संकेत है।

औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर घटकर 4.9 फीसद पर

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 1 जून।

देश का औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर अप्रैल में सालाना आधार पर घटकर 4.9 फीसद दर्ज हुआ। साल 2025 में अप्रैल का यह आंकड़ा 5.7 फीसद पर था। पश्चिम एशिया संकट के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सुस्त वृद्धि के कारण औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि कम रही है।

सोमवार को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर आइआइपी का पहला आंकड़ा जारी किया। इसमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) के संदर्भ में मापे जाने वाले औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि अप्रैल, 2025 में 5.7

फीसद रही थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल 2026 के महीने में खनन और उत्खनन, विनिर्माण, बिजली और गैस आपूर्ति, तथा जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन की विकास दरें क्रमशः 5.1 फीसद, 6.2 फीसद, 4.9 फीसद और 6.6 फीसद रही। आइआइपी का त्वरित अनुमान अप्रैल 2025 के 113.1 के मुकाबले 118.9 रहा। अप्रैल 2026 महीने के लिए खनन और उत्खनन, विनिर्माण, बिजली और गैस आपूर्ति, तथा जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्रमशः 104.6, 119.3, 125.5 और 146.1 रहे। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग का कहना है कि आइआइपी की नई शृंखला पिछली शृंखला की कमियों को दूर करती है। इसमें लघु खनिज भी शामिल हैं।

देश में जन विश्वास अधिनियम लागू

जुर्माना और कार्यवाही से पहले मिलेगी चेतावनी

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 1 जून।

देश में आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने जन विश्वास अधिनियम लागू कर दिया है। यह विधेयक एक जून से लागू किया गया है और इसके आदेश भी जारी किए गए हैं। आदेशों के मुताबिक इस प्रावधान के तहत सरकारी एजेंसियां अपने क्षेत्र में पेशीय नियम प्रक्रिया को आसान बनाने की पहल की है।

सरकार के मुताबिक सरकारी एजेंसियों के साथ कागजी कार्रवाई करते समय होने वाली त्रुटियों की स्थिति में सजा व जुर्माने के प्रावधान रहे हैं। यह प्रावधान सजा से पहले चेतावनी के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। जैसे समय पर कोई जानकारी नहीं देना, फार्म भरने में गड़बड़ी, कागजों में मामूली गड़बड़ी की गलती थी। इन वजह

सरकार के मुताबिक सरकारी एजेंसियों के साथ कागजी कार्रवाई करते समय होने वाली त्रुटियों की स्थिति में सजा व जुर्माने के प्रावधान रहे हैं। यह प्रावधान सजा से पहले चेतावनी के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया।

से आम जनता को जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई से जूझना होता था। नए प्रावधान इस हालात से आम जनता को राहत देंगे, कई मंत्रालयों में यह भी प्रावधान होगा कि आसानी से एक मुश्त शुल्क भुगतान कर मामले का खान्ता किया जा सकेगा। इन प्रावधानों में ऊर्जा मंत्रालय की ओर से किए गए प्रावधान भी शामिल हैं। इन प्रावधानों के संबंध में ही मंत्रालय की ओर से इस विधेयक को लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

ऊर्जा संबंधित विशेषज्ञों के मुताबिक ऊर्जा क्षेत्र

में इस अधिनियम के तहत विद्युत अधिनियम 2003 और दामोदर घाटी निगम के पुराने प्रावधानों में संशोधन किया गया है। ये नियम उपभोक्ताओं के लिए नियम प्रक्रिया को आसान कर देंगे और उन्हें बार-बार जुर्माना या अन्य दंडात्मक कार्रवाई से भी बचाएंगे। केंद्र सरकार ने यह विधेयक लोकसभा में पेश किया था। इसका उद्देश्य 80 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करके अपराधों और दंडों को अपराधों की श्रेणी से बाहर करना था। इस विधेयक ने 2025 में पेश किए गए विधेयक की जगह ली है। इसमें कई जगहों पर दंड की जगह पर मौखिक मूल्य संशोधन का भी प्रावधान है। इन प्रावधानों में पहले ही स्पष्ट किया गया है कि एक निर्धारित समय सीमा के बाद इन प्रावधानों में आर्थिक दंड प्रावधान को बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त नए प्रावधान में आम जनता से संबंधित मामलों में कई स्तर पर चेतावनी देने का प्रावधान भी इसके तहत लाया गया है।

ब्रिक्स संस्कृति कार्यसमूह की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा भारत

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 1 जून।

ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह (सीडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक की मेजबानी भारत करने जा रहा है। जिसका आयोजन 4-5 जून को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जाएगा। इसकी घोषणा सोमवार को संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने प्रेसवार्ता के दौरान की।

यह बैठक में तीन प्रमुख विषयगत प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहेगी। पहला रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योग, कापीराइट व कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूसरा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण व सांस्कृतिक संपदा की वापसी व तीसरा

संस्कृति, जलवायु और सतत विकास। उक्त सभी प्राथमिकताएं सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक 2030 के बाद के सतत विकास एजेंडा में संलग्न होने को दर्शाती हैं। बता दें कि ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक 29-30 अप्रैल 2026 को 'वर्चुअल मोड' में की गई थी। इसके बाद अब दूसरी बैठक 4-5 जून को वाराणसी में होगी। जबकि तीसरी बैठक 5-6 अगस्त को भोपाल में होगी। इस दौरान 6-7 अगस्त को भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव

भी आयोजित किया जाएगा और 7-8 अगस्त को ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक होगी। जबकि इसका समापन 12-14 अक्टूबर 2026 को 'थिएटर महोत्सव' के साथ नई दिल्ली में किया जाएगा।

खबर कोना



उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके बंगले पर शिष्टाचार भेंट की।

रुपया 34 पैसे टूटकर 95.19 प्रति डालर पर

मुंबई, 1 जून (भाषा)।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तथा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच सोमवार को रुपया 34 पैसे लुढ़ककर डालर के मुकाबले 95.19 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि वैश्विक बाजारों में डालर की मजबूती और झरझराल-लेबनान के बीच जारी तनाव से निवेशकों की जोखिम लेने की धारणा प्रभावित हुई, जिसका असर भी रुपए पर पड़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.93 के भाव पर खुला और झरझराल के दौरान यह 94.73 के ऊपरी एवं 95.03 के निचले स्तर तक गया। कारोबार के अंत में यह 95.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से 34 पैसे की गिरावट है। शुक्रवार को रुपया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संभावित हस्तक्षेप के बीच 73 पैसे मजबूत होकर 94.85 प्रति डालर पर बंद हुआ था।

सोना 2,500 टूटा, चांदी 5,000 रुपए कमजोर

नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमत 2,500 रुपए टूटकर 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुए सैन्य संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद वैश्विक बाजारों में आई गिरावट से यहां भी सोने कमजोर पड़ गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 फीसद शुद्धता वाले सोने की कीमत में 2,500 रुपए (1.53 फीसद) की गिरावट आई। शुक्रवार को बंद हुई कीमत 1,62,900 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर यह 1,60,400 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) रह गई। चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट आई और यह 5,000 (या लगभग 2 फीसद) टूटकर 2,69,700 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) रह गई। पिछले सत्र में चांदी की कीमत 2,74,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

चौथे दिन भी गिरा बाजार, सूचकांक 508 अंक फिसला

मुंबई, 1 जून (भाषा)।

अनिश्चित वैश्विक संकेतों के बीच स्थानीय शेयर बाजार सोमवार को चिंतीय, एफएमसीजी एवं वाहन शेयरों में बिकवाली के कारण लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। सूचकांक 508 अंक फिसल गया जबकि निफ्टी में 165 अंक की गिरावट रही। विश्लेषकों के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिका-ईरान संघर्ष को लेकर अनिश्चितता के कारण घरेलू बाजार दबाव में रहा। बीएससे का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक 508.40 अंक यानी 0.68 फीसद गिरकर 74,267.34 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक में 75,367.93 अंक के ऊपरी और 74,203.68 अंक के निचले स्तर को भी छुआ। इस तरह सूचकांक में 1,164.25 अंक का उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया।

यात्री वाहन बिक्री ने मई में पकड़ी रफ्तार

नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

मोटर वाहन कंपनियों ने ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद मई में मजबूत वृद्धि दर्ज की। इस दौरान मारुति सुजुकी और किआ इंडिया ने रिकार्ड बिक्री हासिल की। मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को बताया कि उसकी मासिक बिक्री अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गई, जबकि घरेलू बिक्री मई, 2026 में 1,93,535 इकाई रही जो पिछले साल इसी महीने में 1,38,690 इकाई थी। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) पाशों बनर्जी ने बताया कि ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी से मांग पर असर पड़ने के बावजूद कंपनी ने समय वृद्धि के साथ मजबूत प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर छोटी कारों के खंड पर पड़ता है, खासकर उन ग्राहकों पर जो छोटी कार खरीदते हैं लेकिन हमने हाइमिनी और हाइकांपैक्ट खंड में शानदार वृद्धि हासिल की।

होर्मुज के पूर्व और लाल सागर से होकर गुजरने वाली नौवहन सेवाओं में बढ़ोतरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने फारस की खाड़ी में मौजूदा समुद्री स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए कहा, पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति के बीच होर्मुज के पूर्व और लाल सागर से होकर गुजरने वाली नौवहन सेवाओं में बढ़ोतरी हुई है। होर्मुज के पश्चिमी हिस्से से जहाजों को आवाजाही प्रभावित होने के बाद फरवरी में 127 से बढ़कर अप्रैल में 257 पहुंचने के बाद मई में 245 नौवहन सेवाएं दर्ज की गईं। यह समुद्री व्यापार की मजबूती और नौवहन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के बीच लगातार बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों या भारतीय चालक दल वाले विदेशी जहाजों से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है।

मंत्रालय ने बताया कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों या भारतीय चालक दल वाले विदेशी जहाजों से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। मंत्रालय ने जहाजरानी महानिदेशालय (डीजी शिपिंग) के जरिए अब तक 3,446 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है, जिनमें खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से पिछले 72 घंटों में 24 नाविक शामिल हैं।

अंतर मंत्रालयी संवोधन के दौरान अधिकारी ने बताया कि सरकार ने खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार बनाए रखा है, नियमित आयात, घरेलू उत्पादन और मौजूदा भंडार के समर्थन से खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है।

तृणमूल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर दो विधायकों को निकाला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

तृणमूल कांग्रेस ने कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर अपने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतवत बनर्जी को सोमवार को निष्कासित कर दिया।

इस निष्कासन आदेश से कुछ ही मिनट पहले मुख्यमंत्री शुभेंद्रु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा था कि राज्य विधानसभा में 'फर्जी हस्ताक्षर' मामले के संबंध में शिकायतें इन दोनों विधायकों ने दर्ज कराई थीं। यह मामला तृणमूल द्वारा शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के रूप में समर्थन दिए जाने के पत्र से जुड़ा है। दोनों विधायकों को भेजे गए पत्र में कहा गया है,

काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक छह जून को भारत लौटेंगे

नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को कहा कि वह परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों के संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की शुरुआत के लिए छह जून को भारत लौटेंगे। वर्तमान में अमेरिका में रह रहे दीपके ने 'इंस्टाग्राम' पर जारी एक वीडियो में समर्थकों और छात्रों से दिल्ली में उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी भारत के संविधान के मार्ग पर चलते हुए एकजुट हों और शांतिपूर्वक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो उन्हें हमारी बात जरूर सुननी पड़ेगी। दीपके इस समय अमेरिका के बोस्टन शहर में हैं, जहां उन्होंने हाल ही में जनसंपर्क में सनातकोटर की पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने समर्थकों से छह जून को हवाई अड्डे पर उनसे मिलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं शनिवार, छह जून को सुबह दिल्ली पहुंचूंगा। कृपया हवाई अड्डे पर मुझे मिलें और हम सब मिलकर संसद मार्ग थाने जाकर जंतर-जंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगेंगे। सीजेपी के संस्थापक ने आशंका जताई कि भारत लौटने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

दीपके ने कहा, लेकिन उनका मानना है कि उनका नियोजित विरोध प्रदर्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा की संवैधानिक गारंटी के तहत संरक्षित है। दीपके ने हालांकि कहा कि वह परिवार को मिला रही धमकियों को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से मिली धमकियों की ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन मेरे परिवार को मिली धमकियों को लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूँ। क्योंकि मेरे परिवार ने ऐसा करने का फैसला नहीं किया था, यह मेरा निर्णय था। उन्हें इसमें घसीटा नहीं जाना चाहिए।

पश्चिम एशिया संघर्ष : युद्धविराम की स्थिति बनी नाजुक

अमेरिका ने ईरानी सैन्य स्थलों पर बमबारी की, कुवैत पर हुए ड्रोन व मिसाइल हमले

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

अमेरिका ने सोमवार को कहा कि इस सप्ताह में तेहरान द्वारा एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद उसने ईरान में रडार और ड्रोन ठिकानों पर बमबारी की।

अमेरिका के बयान के बाद ईरान ने कहा कि उसने कुवैत में अमेरिकी सैनिकों को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिन्हें अमेरिका ने मार गिराने का दावा किया है। ये हमले ईरान युद्ध में कई सप्ताह से लागू युद्धविराम की नाजुक स्थिति को दशाते हैं। अमेरिकी और ईरानी अधिकारी इस युद्धविराम की अवधि को बढ़ाने के लिए समझौते पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमले लगातार जारी हैं।

ईरान होर्मुज जलमार्ग पर अपनी पकड़ बनाए हुए है जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है। कभी फारस की खाड़ी के इस संकरे मुहाने से तेल और प्राकृतिक गैस के वैश्विक कारोबार का पांचवां हिस्सा गुजरता था। ब्रिटिश सेना ने बताया कि सोमवार अपराह्न इराक के तट पर एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। इजराइल और लेबनानी चरमपंथी समूह हिज्बुल्ला के बीच लड़ाई तेज हो गई है। इजराइल ने लेबनान में अपना कब्जा काफी अंदर तक बढ़ा दिया है, और हिज्बुल्ला - जो अपने मुख्य समर्थक ईरान के समर्थन में युद्ध में शामिल हुआ - इजराइल पर ड्रोन हमले जारी रखे हुए है।

अमेरिकी सेना की 'सेंट्रल कमांड' ने कहा कि उसने शनिवार और रविवार को ईरान में गेरुक शहर और केशम द्वीप के आसपास हमले किए। 'सेंट्रल कमांड' ने कहा, 'सीमित और



हमले में कोई हताहत नहीं : ईरान

ईरानी मीडिया ने बताया है कि अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास बंदरगाह के पास हमला किया, जिससे कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्पस ने बाद में कहा कि उसने बंदर अब्बास हमले के जवाबी कार्रवाई में एक अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, और वेतानी दी कि यदि अमेरिका का आक्रमण जारी रहा तो और भी निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।

सोच-समझकर किए गए थे हमले ईरान की आक्रामक कार्रवाइयों के जवाब में हुए थे, जिनमें अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र के ऊपर उड़ान भर रहे 'अमेरिकी एमक्यू-1' ड्रोन को मार गिराना शामिल है।

उसने कहा, 'अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों, एक जमीनी नियंत्रण केंद्र और दो ऐसे ड्रोन को नष्ट कर दिया जो क्षेत्रीय जलक्षेत्र से गुजर रहे पोतों के लिए स्पष्ट खतरा पैदा कर रहे थे।' प्रीडेटर ड्रोन को अमेरिकी वायुसेना सेवा से हटा चुकी है और अब वह 'एमक्यू-9 रीपर' ड्रोन का इस्तेमाल करती है लेकिन अमेरिकी

थल सेना अब भी प्रीडेटर ड्रोन का उपयोग करती है। अमेरिकी सेना ने कहा कि इन हमलों में कोई अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ। इस बीच कुवैत ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने के लिए सोमवार तड़के कार्रवाई शुरू कर दी।

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनएफ की खबर के अनुसार, ईरानी अर्द्धसैन्य बल 'रिवोल्यूशनरी गार्ड' ने एक बयान में बताया कि अमेरिकी बलों ने एक द्वीप पर दूरसंचार टावर को निशाना बनाया। 'रिवोल्यूशनरी गार्ड' ने कहा कि उसने जवाबी हमला किया लेकिन यह नहीं बताया कि हमला

'मिसाइलों व ड्रोन का सामना किया'

कुवैत की सेना ने कहा कि उसके हवाई सुरक्षा तंत्र ने 'दुश्मन' मिसाइलों और ड्रोन का सामना किया, लेकिन उसने यह जानकारी नहीं दी कि यह हमला कहां से हुआ था। यह नए हमले तीन महीने पुराने युद्ध को खत्म करने के लिए चल रही बातचीत के दौरान हुए। यह युद्ध 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के साथ शुरू हुआ था, जिसमें अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और वैश्विक ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं।

ईरानी ड्रोन को मार गिराया : अमेरिका

एक अमेरिकी अधिकारी ने रायटर्स को बताया कि अमेरिकी सेना ने रात के समय ईरान में नए हमले किए। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अमेरिकी सेना ने कई ईरानी ड्रोन को भी रोक और मार गिराया, जो इसी तरह का खतरा पैदा कर रहे थे।

कहा किया गया। ब्रिटिश सेना ने बताया कि सोमवार को इराक के उम कसर तट के पास एक मालवाहक जहाज पर हमला किया गया, जिससे एक 'बड़ा विस्फोट' हुआ। हालांकि ईरान ने पहले भी इराक के तट पर जहाजों पर हमले किए हैं, लेकिन सेना ने कोई विवरण नहीं दिया और किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सोमवार को एक बार फिर अमेरिका पर लगातार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'शुरू से ही हम जानते थे और अब भी जानते हैं कि हम अविश्वास के माहौल में बातचीत कर रहे हैं।'

कर्नाटक मंत्रिमंडल गठन पर आज सहमति संभव सिद्धरमैया और शिवकुमार की शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री पद का फैसला होने के बाद अब डीके शिवकुमार से मंत्रिमंडल सहयोगियों की तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए सोमवार को दिल्ली में कर्नाटक के नेताओं का ताता लगा रहा और इन नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की।

माना जा रहा है कि इन बैठकों में नए मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल सहयोगियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। डीके शिवकुमार के अतिरिक्त पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी सोमवार को दिल्ली में ही मौजूद रहे। पार्टी के नेताओं से मुलाकात के बाद कर्नाटक के मनोनीत मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिल्ली में



मुख्यमंत्री तीन जून को शपथग्रहण समारोह, राहुल गांधी भी होंगे शामिल।

कर्नाटक भवन पहुंचे। इससे पहले डीके शिवकुमार दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से भी

मुलाकात की। सोमवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया दिल्ली में ही मौजूद थे। इसके अतिरिक्त कर्नाटक कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर पहुंच कर उनके मुलाकात की।

कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से मिलने दिल्ली के एक होटल पहुंचे। कांग्रेस नेता एच.के. पाटिल ने कर्नाटक में नई सरकार के गठन पर कहा, 'पार्टी में सबकुछ सामान्य चल रहा है। पार्टी के नेताओं में बहुत सहमति है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष से मिला और अपने कर्तव्यों का पालन करने में उनके मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता था।

कोर्ट ने सीबीआइ को झुनझुनवाला को गिरफ्तार करने की अनुमति दी

मुंबई/नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

मुंबई को एक अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को उद्योगपति अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक ऋणों के कथित दुरुपयोग से संबंधित मामले में गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी।

मामला कंपनी द्वारा कथित ऋण धोखाधड़ी में भारतीय स्टेट बैंक को हुए 2,929.05 करोड़ रुपए के नुकसान से संबंधित है। झुनझुनवाला को नई दिल्ली की तिहाड़ केंद्रीय जेल से एक पेशी वारंट पर सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश जेपी दरेकर के सामने पेश किया गया। झुनझुनवाला ईडी की जांच वाले एक संबंधित घनशोधन मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें

पेश किए जाने के बाद, सीबीआइ ने विशेष लोक अभियोजक ए लियोसिन के माध्यम से आरोपी को हिरासत में लेने और औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया।

झुनझुनवाला की ओर से पेश अधिवक्ता रीति उपाध्याय और मुक्ति जैन ने तर्क दिया कि दिल्ली की एक अदालत द्वारा जारी किए गए पेशी वारंट के अनुसार, अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के पूर्व कार्यकारी को पांच जून को अदालत के समक्ष पेश किया जाना था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि उस तारीख से पहले अदालत के समक्ष उनकी पेशी अवैध है। अदालत ने सीबीआइ के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसमें आरोपियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी गई थी।

मुलाकात

नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल एन एस राजा सुब्रमणिया व उनकी पत्नी महालाक्ष्मी सुब्रमणिया।

मौसम विभाग ने कहा

अनुमान

कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चिंता का विषय

मानसून के दो-तीन दिन में केरलम पहुंचने की संभावना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

देश की मुख्य भूमि पर मानसून का इंतजार खत्म होने को है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को कहा कि दो से तीन दिन में दक्षिण-पश्चिम मानसून के केरलम पहुंचने की संभावना की पूरी संभावना है। आमतौर पर मानसून एक जून को केरलम में पहुंच जाता है।

मौसम विभाग ने कहा कि अगले दो-तीन दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप समूह, केरलम व तमिलनाडु के कुछ हिस्से, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य व उत्तर-पूर्व बंगाली की खाड़ी के कुछ और हिस्सों तथा दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं।

जून से सितंबर 2026 के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम मौसमी वर्षा होने की सबसे अधिक संभावना है। इसके अलावा के तौर पर उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्र, दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से और पूर्वी-मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के कुछ अलग इलाके शामिल हैं, जहां सामान्य से लेकर सामान्य

तीन जून से उत्तर-पश्चिमी भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है। उत्तर-पश्चिमी भारत के कई राज्यों में तापमान में क्रमिक चार से छह डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हो सकती है।

विभाग ने शुक्रवार को कहा था कि देश में मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है, जो लंबी अवधि के औसत का 90

से अधिक वर्षा होने की संभावना है। देश की अधिकांश वर्षा-आधारित कृषि भूमि के लिए दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा भी सामान्य से कम रहने की संभावना है, जो लंबी अवधि के औसत के 94 फीसद से नीचे होगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश के सामान्य रहने की सबसे अधिक संभावना है

फीसद होगी। इसके साथ ही साल 2026 देश में 10 साल का सबसे सूखे वर्ष हो सकता है। विभाग ने अप्रैल में जारी अपने पिछले पूर्वानुमान को घटा दिया है। साल 1971 से साल 2020 तक के आंकड़ों के आधार पर, जून से सितंबर के दौरान देश में मानसून वर्षा का लंबी अवधि का औसत 87 सेंटीमीटर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 'कमी वाले' मानसून (लंबी अवधि के

औसत का 90 फीसद से कम) की 60 फीसद संभावना है, 'सामान्य से कम' मानसून (लंबी अवधि के औसत का 90-95 फीसद) की 24 फीसद संभावना है, 'सामान्य' मानसून (लंबी अवधि के औसत का 96-104 फीसद) की 14 फीसद संभावना है, 'सामान्य से अधिक' मानसून (लंबी अवधि के औसत का 105-110 फीसद) की दो फीसद संभावना है और 'अत्यधिक' मानसून (लंबी अवधि के औसत का 110 फीसद से अधिक) की शून्य संभावना है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने कहा कि हमने लंबी अवधि के औसत का 90 फीसद पूर्वानुमान, इस आधार पर जारी किया है कि इस मौसम के दौरान हमें कुल कितनी बारिश मिलने की संभावना है। इसलिए हम गतिशील कारकों पर भी नजर रखते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय है।

खबर कोना



कुलगाम में सोमवार को नशामुक्त पदयात्रा के दौरान बच्चों के साथ जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा।

अमेरिकी सेना ने होर्मुज से 70 वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित निकलवाया

वाशिंगटन, 1 जून (भाषा)।

पिछले तीन हफ्तों में अमेरिकी सशस्त्र बलों ने लगभग 70 वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलमार्ग से सुरक्षित निकाला है। ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध की शुरुआत के तीन महीने बाद से यह जलमार्ग जोखिम भरा बना हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन हफ्तों में अमेरिकी सेंट्रल कमान ने फारस की खाड़ी में आने-जाने वाले लगभग 70 वाणिज्यिक जहाजों का जलमार्ग से गुजरने में मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि संकरे जलमार्ग से गुजरते समय पकड़े जाने से बचने के लिए ज्यादातर जहाजों ने अपने ट्रांसपॉंडर बंद कर दिए थे। बताया गया कि 28 फरवरी को युद्ध

शुरू होने से पहले, प्रतिदिन 100 से अधिक वाणिज्यिक जहाज होर्मुज से होकर गुजरते थे। ईरान और ओमान से घिरे इस संकरे जलमार्ग से वैश्विक तेल आपूर्ति की 20 फीसद माल ढुलाई होती है। अधिकारियों ने यह बताने से इनकार कर दिया कि किस प्रकार के जहाज वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया, लेकिन अधिकारी ने संकेत दिया कि एक मार्ग ईरानी तटरक्षा के करीब नहीं था। अधिकारियों ने कहा कि ईरान की अनुमति के बिना ईरान के पास से गुजरने वाले जहाजों पर ईरानी ड्रोन या मिसाइलों द्वारा हमले का खतरा निश्चित है।

गुजर रहे थे और उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया, लेकिन अधिकारी ने संकेत दिया कि एक मार्ग ईरानी तटरक्षा के करीब नहीं था। अधिकारियों ने कहा कि ईरान की अनुमति के बिना ईरान के पास से गुजरने वाले जहाजों पर ईरानी ड्रोन या मिसाइलों द्वारा हमले का खतरा निश्चित है।

नागेंद्र नाथ त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठक नियुक्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के वरिष्ठ नेता नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को राष्ट्रीय संगठक नियुक्त किया है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। त्रिपाठी बिहार और झारखंड के लिए भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे थे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) अरुण सिंह ने एक अधिसूचना में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को पार्टी का राष्ट्रीय संगठक (विशेष कार्यकर्ता संपर्क) नियुक्त किया है। उनका केंद्र दिल्ली रहेगा।

राज्यसभा की 27 व तीन विधानसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित

नई दिल्ली, 1 जून (ब्यूरो)।

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को देश में होने वाले 27 राज्यसभा और तीन विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों पर आगामी 18 जून को मतदान होगा। यह प्रक्रिया सुबह आठ बजे से शुरू होगी और चार बजे तक होगी। मतदान के दिन ही निर्वाचन आयोग मतों की गणना की प्रक्रिया शुरू करेगा। इन चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आदेश जारी होने के साथ ही शुरू हो गई है और आगामी आठ जून तक इन सीटों के लिए नामांकन किया जाएगा। नामांकन की जांच नौ जून होगी और नामांकन करने वाला उम्मीदवार 11 जून तक अपना नामांकन वापस ले सकता है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस प्रक्रिया के तहत दस राज्यों की 24 सीटों के लिए मतदान होगा। इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा की सीटें शामिल हैं। इसी प्रकार बिहार राज्य विधानसभा की नौ सीटों के लिए दिवाबिक चुनाव होगा और एक सीट के लिए उपचुनाव कराय जाएगा। कर्नाटक में विधानसभा की सात सीटों के लिए चुनाव कराय जाएगा।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

YAASHVI JEWELLERS LIMITED

Corporate Identification Number: U27200RJ2016PLC056519

Our Company was incorporated as "Yaashvi Jewellers Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 vide certificate of incorporation dated December 13, 2016 issued by Registrar of Companies/ Central Registration Centre. Subsequently the status of the Company was changed to public limited and the name of our Company was changed to "Yaashvi Jewellers Limited" vide Special Resolution passed by the Shareholders at the Extra Ordinary General Meeting of our Company held on September 12, 2024. The fresh certificate of incorporation consequent to conversion was issued on December 13, 2024, by Central Processing Centre. The Corporate Identification Number of our Company is U27200RJ2016PLC056519. For further details on Incorporation and Registered Office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 157 of the Prospectus.

Registered Office: Plot No. 486, Nemi Sagar Colony, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan, India, 302021.
Telephone: +91 9529833397 | Email: investor@yaashvijewellers.com | Website: www.yaashvijewellers.com
Contact Person: Mr. Kalu Ram Kumawat, Company Secretary and Compliance Officer



THE PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE MS. ANKITA AGARWAL AND MR. ANKIT AGGARWAL

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE (BSE SME)."

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 52,86,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF YAASHVI JEWELLERS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "YAASHVI" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 83/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING TO ₹ 4,387.71 LAKHS ("PUBLIC ISSUE"). THE ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF 2,67,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 83/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ 221.78 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 50,19,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 83/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ 4,165.94 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.00% and 28.48% RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ISSUE PRICE: ₹ 83/- PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH.

THE ISSUE PRICE IS 8.3 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

ISSUE PROGRAM

ISSUE OPENED ON: MONDAY, MAY 25, 2026

ISSUE CLOSED ON: WEDNESDAY, MAY 27, 2026

Risks to Investors:

- Risk to Investors: Top 5 Risk factors:**
 - We have certain outstanding litigation against us, an adverse outcome of which may adversely affect our business, reputation and results of operations.
 - We depend on few suppliers for our raw materials required for our operations and we have not entered into any long-term agreements. Any delays, interruptions or reduction in the supply of raw materials to manufacture our products and any abrupt fluctuations in the prices of our raw materials may adversely affect the pricing of our products and may have an impact on our business, results of operation, financial condition and cash flows.
 - We depend on certain customers for a significant portion of our revenues. Also, our Company in the usual course of business does not have any long-term contracts with its customers and we rely on purchase orders for delivery of our products and our customers may cancel or modify their orders, change quantities, delay or change their sourcing strategy. Loss of one or more of our top customers or a reduction in their demand for our products or reduction in revenue derived from them may adversely affect our business, results of operations and financial condition.
 - Our jewellery business faces risks from market volatility and changing customer preferences. Fluctuations in commodity prices like gold and silver could impact our costs and profitability. Our ability to anticipate changes in industry trends to meet customers' demands and any variations in the government regulations/policies or technology upgradation is a significant factor to remain competitive, any failure to identify and understand the trends may materially adversely affect our business.
 - Majority of our revenue from operation is derived from manufacturing of plain gold chains. Any reduction in the sale of plain gold chains, or our inability to manufacture and sell plain gold chains, may have an adverse effect on our business, results of operations, cash flows and financial condition.
- Our Equity Shares have never been publicly traded and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market, and the price of our Equity Shares may be volatile, and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.
- The Merchant Banker associated with the Issue has handled following public issues in the past three years which have closed below the Issue Price on Listing date:

Name of Lead Manager	Total Issues	Issues that closed below IPO price as on listing date
Smart Horizon Capital Advisors Private Limited	23	05
Total	23	05

4. The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is as follows:

Sr. No.	Name	No of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹) *
Promoters			
1.	Ms. Ankita Agarwal	55,07,362	1.70
2.	Mr. Ankit Aggarwal	61,24,982	7.38

*As certified by Statutory Auditor of our Company, by way of their certificate dated May 08, 2026.

5. Weighted average cost of acquisition during the 18 months preceding the date of the Prospectus:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in ₹) *	Issue Price is '83.00' times the Weighted Average Cost of Acquisition
Weighted average cost of acquisition of primary issuances	Nil	NA
Weighted average cost of acquisition for secondary transactions	58.00	1.43

*As certified by Statutory Auditor of our Company, by way of their certificate dated May 08, 2026.

The Issue was being made through the Fixed Price process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the SCRR this Issue is being made for at least 25% of the post-Issue paid-up Equity Share capital of our Company. This Issue is being made through Fixed Price process in accordance and compliance with Chapter IX and other applicable provisions of SEBI ICDR Regulations wherein a minimum 50% of the Net Issue is allocated for Individual Investors who applies for minimum application size and the balance shall be offered to individual applicants other than Individual Investors who applies more than minimum application size and other investors including corporate bodies or institutions, QIBs and Non-Institutional Investors. However, if the aggregate demand from the Individual Investors is less than 50%, then the balance Equity Shares in that portion will be added to the other than Individual Investors portion offered to the remaining investors including QIBs and NIs and vice-versa subject to valid applications being received from them at or above the Issue Price. Additionally, if the Individual Investors category is entitled to more than 50% on proportionate basis, the Individual Investors shall be allocated that higher percentage. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the respective bank accounts and / or UPI IDs, in case of UPI Applicants, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same. For details in this regard, specific attention is invited to "Issue Procedure" beginning on page 277 of this Prospectus.

The Issue was subscribed to the extent of 6.35 times as per the bid books of BSE (the "Bid Files") after removing multiple and duplicate bids.

The Issue received 1,978 applications for 2,86,14,400 Equity Shares before technical rejections and after invalid bids Multiple/Duplicate/bids, UPI Mandates not accepted by investors, bids rejected under application banked but bid not registered resulting in 5.41 times subscription (including reserved portion of market maker). The Details of the Applications received from various categories (before technical rejection) are as under:

Detail of the Applications Received:

Sr. No.	Category	Number of Applications	No. of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (₹)
1.	Market Maker	1	2,67,200	2,67,200	1.00	2,21,77,600
2.	Individual Investors	1,382	44,22,400	25,12,000	1.76	36,70,59,200
3.	Other than Individual Investors	595	2,39,24,800	25,07,200	9.54	1,98,57,58,400
Total		1,978	2,86,14,400	52,86,400	5.41	2,37,49,95,200

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange - BSE on May 29, 2026.

1) **Allocation to Market Maker (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to Market Maker, who have applied at Issue Price of ₹ 83/- per equity shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 time i.e., for 2,67,200 shares the total number of shares allotted in this category is 2,67,200 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of applications received	% to total	Total no. of shares applied in this category	% of total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total Number of shares allotted	Surplus/ Deficit
2,67,200	1	100.00	2,67,200	100.00	2,67,200	1:1	2,67,200	0.00
Total	1	100	2,67,200	100	2,67,200			

2) **Allocation to individual investors (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to individual investors, who have applied at cut-off Price or at or above the Issue Price of ₹ 83.00 per equity shares, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.75 times i.e., for 43,90,400 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 25,12,000 Equity Shares to 785 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of applications received	% to total	Total no. of shares applied in this category	% of total	Proportionate shares available	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total Number of shares allotted
3,200	1,372	100.00	43,90,400	100.00	25,12,000	3,200	785:1372	25,12,000
Total	1,372	100	43,90,400	100	25,12,000	3,200	785:1372	25,12,000

3) **Allocation to Other than Individual Investors (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to Other than Individual Investors, who have applied at Issue Price of ₹ 83.00 per equity shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 9.52 times i.e., for 2,38,60,800 shares. The total number of shares allotted in this category is 25,07,200 Equity Shares to 522 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	Category	No. of Application Received	% to Total	Total No. of Equity Shares applied	% of Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	4800	438	74.24	2102400	8.81	4800	387:438	1857600
2	6400	8	1.36	51200	0.21	4800	7:8	33600

3	9600	2	0.34	19200	0.08	4800	0:0	0
4	11200	7	1.19	78400	0.33	4800	6:7	28800
5	12800	89	15.09	1139200	4.77	4800	79:89	379200
6	20800	1	0.17	20800	0.09	4800	1:1	4800
7	30400	4	0.68	121600	0.51	4800	3:4	14400
8	32000	2	0.34	64000	0.27	4800	0:0	0
9	44800	1	0.17	44800	0.19	4800	1:1	4800
10	48000	1	0.17	48000	0.20	4800	1:1	4800
11	51200	2	0.34	102400	0.43	4800	0:0	0
12	59200	3	0.51	177600	0.74	4800	2:3	9600
13	60800	1	0.17	60800	0.25	4800	1:1	4800
14	64000	2	0.34	128000	0.54	4800	0:0	0
15	73600	1	0.17	73600	0.31	4800	1:1	4800
16	80000	1	0.17	80000	0.34	4800	1:1	4800
17	102400	1	0.17	102400	0.43	4800	1:1	4800
18	105600	1	0.17	105600	0.44	4800	1:1	4800
19	113600	1	0.17	113600	0.48	4800	1:1	4800
20	120000	2	0.34	240000	1.01	4800	0:0	0
21	121600	4	0.68	486400	2.04	4800	3:4	14400
22	128000	1	0.17	128000	0.54	4800	1:1	4800
23	144000	1	0.17	144000	0.60	4800	1:1	4800
24	156800	1	0.17	156800	0.66	4800	1:1	4800
25	160000	1	0.17	160000	0.67	4800	1:1	4800
26	179200	1	0.17	179200	0.75	4800	1:1	4800
27	190400	1	0.17	190400	0.80	4800	1:1	4800
28	196800	1	0.17	196800	0.82	4800	1:1	4800
29	240000	2	0.34	480000	2.01	4800	0:0	0
30	241600	1	0.17	241600	1.01	4800	1:1	4800
31	243200	1	0.17	243200	1.02	4800	1:1	4800
32	264000	1	0.17	264000	1.11	4800	1:1	4800
33	275200	1	0.17	275200	1.15	4800	1:1	4800
34	361600	1	0.17	361600	1.52	4800	1:1	4800
35	422400	1	0.17	422400	1.77	4800	1:1	4800
36	5019200	3	0.51	15057600	63.11	4800	2:3	9600
52,800 shares to be allotted to unsuccessful allottees (Sr. Nos. 3, 8, 11, 14, 20, 29) at 4,800 shares each in the ratio of 1:12								
1,600 Additional share will be allotted to successful allottees from Sr no. 2 to 36 = 1,600 shares in ratio of 1:135								
Total		--	100.00	---	100.00	---	1:135	1600
Total		--	100.00	---	100.00	---	1:135	25,07,200

The Board of Directors of the Company at its meeting held on May 29, 2026 has approved the Basis of Allocation of Equity Shares as approved by the Designated Stock Exchange viz. BSE and has authorized the corporate action for issue of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN-cum-allotment advices and/or notices will forward to the email id's and address of the Applicants as registered with the depositories / as filled in the application form on or before June 01, 2026. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking the amount will process on or prior to June 01, 2026. In case the same is not received within ten days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the BSE SME within Three working days from the date of the closure of the Issue.

CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS FILED WITH REGISTRAR OF COMPANIES, JAIPUR ON MAY 19, 2026

This Corrigendum is with reference to the Prospectus filed on May 19, 2026. In this regard, please note the following:

- The name of company shall be read as "YAASHVI JEWELLERS LIMITED" instead of "YAASHVI JEWELLERS LIMITED" on the inside cover page.
- The Investor grievance e-mail and Website of the Registrar to The Issue shall be interchanged on the inside cover page.
- Borrowing powers disclosure on page no. 164 of the prospectus shall be read as (Rupees Two Hundred Crores only) in amount disclosed in words.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 19, 2026 ("Prospectus") filed with Registrar of Companies, Jaipur.

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the issue, BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED at www.bigshareonline.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:



BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
Office No. S6 - 2, 6th Floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves, Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093.
Tel. No.: 022 - 6263 8200 | E-mail: ipo@bigshareonline.com
Investors Grievance e-mail: investor@bigshareonline.com | Website: www.bigshareonline.com
Contact Person: Mr. Asif Sayyed | SEBI Registration No.: INR000001385

For YAASHVI JEWELLERS LIMITED

On behalf of the Board of Directors

Sd/-

Mr. Ankit Aggarwal

Designation: Whole Time Director

DIN: 06568063

Date: June 01, 2026

Place: Jaipur

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF YAASHVI JEWELLERS LIMITED.

Yaashvi Jewellers Limited is proposing, subject to market conditions, public issue of its equity shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Jaipur. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.shcapl.com website of the BSE at www.bseindia.com and website of Issuer Company at https://yaashvijewellers.com/. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors shall refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

AdBaz

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



Please Scan this QR code to view Prospectus

HARIKANTA OVERSEAS LIMITED

CORPORATE IDENTITY NUMBER: U17299GJ2018PLC104835

Our Company was originally incorporated as "Harikanta Overseas Private Limited", a Private Limited Company under the provisions of the Companies Act, 2013. Pursuant to a certificate of incorporation dated October 22, 2018 Issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, pursuant to a Special Resolution of our Shareholders passed in the Extra-Ordinary General Meeting held on January 27, 2025 our Company was converted from a Private Limited Company to Public Limited Company and consequently, the name of our Company was changed to "Harikanta Overseas Limited" and a fresh certificate was issued on February 22, 2025 by the Registrar of Companies, Central Registration Centre. For further details, please refer the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 132 of the Prospectus.

Registered Office: 28, Sairam Ind Estate Bamroli, Surat-394107, Gujarat, India
Tel No.: +9198986 82560; E-Mail: info@harikantaoverseas.com; Website: www.harikantaoverseas.com
Contact Person: Swati Malu, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: HARDIK GOTAWALA, ABHISHEK GOTAWALA, NILESH GOTAWALA

INITIAL PUBLIC OFFER OF EQUITY SHARES ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED (BSE) IN COMPLIANCE WITH CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018

Our Company is engaged in the manufacturing of Synthetic textile fabrics. Our product portfolio includes Ikat fabrics, polyester garment fabrics, saree fabrics, dhupion fabrics, poly linen, and natural fiber. We primarily cater fabric to women's wear, producing fabrics for sarees, dress materials, and kurtas, while also offering fabrics for men's kurtas. Although our fabrics have multiple end uses, the majority of them are utilized in the manufacturing of different types of sarees. The origins of our business can be traced back to our Promoters' grandfather, Mr. Harivadan Gangaram Gotawala, who laid the foundation by operating manual power looms from his residence. Over time, the enterprise was expanded by his son, Mr. Kamlesh Gotawala, who scaled up operations and established a market presence. Following his untimely demise in 1997, his brother, Mr. Nilesh Gotawala, assumed responsibility for the business and continued to nurture and grow its operations. The next generation—Mr. Hardik Gotawala, son of Kamlesh Gotawala, and Mr. Abhishek Gotawala, son of Nilesh Gotawala—subsequently joined the family enterprise. They brought with them fresh ideas, energy, and a focus on efficiency and modern production practices. Their active involvement contributed to enhanced productivity, diversification of the product range, and the transformation of the business into a broader textile manufacturing enterprise. Today, under the vision and combined experience of Mr. Hardik Gotawala, Mr. Abhishek Gotawala, and Mr. Nilesh Gotawala, the Company has evolved into a diversified manufacturer of textile products while strengthening its domestic presence through its associate concerns. For further details regarding associate concerns, kindly refer to the chapter titled Promoter and Promoter Group on page no. 149 of the Prospectus.

With the objective of broadening business horizons and accessing international markets, the Promoters incorporated Harikanta Overseas Private Limited on October 22, 2018. This marked a milestone in their entrepreneurial journey, creating a platform for global trade. The company commenced exports of products such as Ikat fabrics and Dhupion fabrics, which not only reinforced its market presence but also expanded its customer base beyond India. This step diversified the group's business portfolio and placed it on a path of growth with an emphasis on global expansion. With the objective of supplying products to overseas customers, we have set up a manufacturing unit at Surat, Gujarat. Our current manufacturing facility is spread across 953.93 sq. mtrs. at Plot No.-16, 23,24,25,26,27 and 28 of Sai Ram Industrial Estate-2, Bamroli Gam, Bamroli, Surat, Gujarat, 394107.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 26,70,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH OF HARIKANTA OVERSEAS LIMITED ("HOL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹91 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹81 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹2429.70 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 1,34,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹91 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹81 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹122.30 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E., NET ISSUE OF 25,35,600 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT A PRICE OF ₹91 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹2307.40 LAKHS IS HEREIN REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.06% AND 25.70% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

**ISSUE PRICE IS ₹91 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹10 EACH.
THE ISSUE PRICE IS 9.1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.**

BID/ISSUE PROGRAMME

BID/ISSUE OPENED ON: WEDNESDAY, MAY 20, 2026

BID/ISSUE CLOSED ON: WEDNESDAY, MAY 27, 2026

RISKS TO INVESTORS

Summary Description of Key Risk Factors Based on Materiality:

- We have not yet placed orders in relation to the capital expenditure to be incurred for the proposed, purchase of equipment / machineries. In the event of any delay in placing the orders for Machineries or in the event the vendors are not able to provide the equipment / machineries in a timely manner, or at all, the same may result in time and cost over-runs.
- Our business is significantly dependent on yarn and other related raw materials, and fluctuations in their prices or availability, as well as concentration of our supplier base, may adversely affect our operations, margins, and profitability.
- Our operations are energy-intensive and any disruption in power supply or increase in energy costs may adversely affect our business and financial performance.
- Potential Exposure to Competition Despite Non-Compete Agreements with Promoter Group Entities
- Potential Conflicts of Interest Arising from Promoters' Proprietary Businesses and Their Operational Overlap with Our Company
- Our business is working capital intensive and any inability to secure adequate financing may adversely impact operations.
- Dependence on third-party and subsidiary job work arrangements
- We have experienced negative cash flows in previous years / periods. Any operating losses or negative cash flow in the future could adversely affect our results of operations and financial condition.
- There may have been certain instances of non-compliances with respect to certain corporate actions taken by our Company in the past. Consequently, we may be subject to regulatory actions and penalties.
- Our business is seasonal in nature, which could adversely affect our business operations and financial performance.

Details of suitable ratios of the company for the latest full financial year

1. Basic and Diluted Earnings per Share (EPS)

Year ended	Weights	Basic and Diluted EPS
March 31, 2023	1	0.40
March 31, 2024	2	1.27
March 31, 2025	3	6.69
Weightage Average EPS	6	3.84
November 30, 2025*		10.61

*Annualized

Note:
Basic and Diluted EPS = Net Profit (Loss) after tax as restated attributable to Equity Shareholders / weighted average no of equity shares outstanding during the year as per restated Consolidated financials.

The figures disclosed above are based on the Consolidated Restated Summary Financial Information of our Company for the Period ended on November 30, 2025 and year ended March 31, 2025 and Standalone Restated Financial Statements of the Company for the financial year ended on March 31, 2024 and March 31, 2023

2. Price to Earnings (P/E) ratio in relation to Issue Price ₹91 per Equity Share of ₹10/- each fully paid up

Particulars	P/E at the lower end of the price band	P/E at the upper end of the price band
P/E ratio based on Basic and diluted EPS as at March 31, 2025	12.86	13.60
P/E ratio based on Weighted Average Basic and diluted EPS	22.43	23.73
Industry PE		
Highest	35.61	
Lowest	19.44	
Industry Average	27.53	

3. Return on Net worth (RoNW)

Return on Net Worth (RoNW) as per restated financial statements

Year Ended	RoNW (%)	Weight
March 31, 2023	1	22.00
March 31, 2024	2	41.67
March 31, 2025	3	32.41
Weighted Average	6	33.76
November 30, 2025		40.65

Note: Return on Net worth has been calculated as per the following formula:

1) Return on Net Worth (%) = Net Profit after tax attributable to owners of the Company, as restated / Net worth as restated as at year end.

2) Weighted average Net Worth = Aggregate of year-wise weighted RoNW divided by the aggregate of weights i.e. (RoNW x Weight) for each year/Total of weights.

4. Net Asset Value (NAV)

Particulars	₹ per share
Net Asset Value per Equity Share as of November 30, 2025	26.08
Net Asset Value per Equity Share as of March 31, 2025	19.16
Net Asset Value per Equity Share after IPO	38.60
Issue Price	91
NAV Post Issue	
- At Floor Price	37.25
- Issue Price	38.60

Note: Net Asset Value has been calculated as per the following formula:

NAV = $\frac{\text{Net worth excluding revaluation reserve}}{\text{Outstanding number of Equity shares during the year}}$

5. Comparison with industry peers

Companies	CMP*	EPS	PE Ratio	RoNW (%)	NAV (Per Share)	Face Value	Revenue from Operation	Total Income
Harikanta Overseas Limited*	91**	6.69	13.60	33.00	19.13	10.00	3,517.30	3,546.57
Peer Group								
Betex India Limited\$	365.00	13.03	28.01	5.73	227.34	10.00	9,637.99	9,714.55
Swasti Vinayaka Synthetics Limited\$	3.45	0.27	12.78	10.54	2.55	1.00	3,838.06	3,855.83

*CMP as on March 05, 2026

** CMP of our company is considered as an Issue Price.

Amount taken from Restated Consolidated Financials as on March 31, 2025.

\$ Consolidated financial Statement of peers are not Available.

Source: www.bseindia.com

Notes:

- Considering the nature and size of the business of our Company the peers are not strictly comparable. However, above company is included for broad comparison.
- The figures for Harikanta Overseas Limited are based on the restated consolidated financial statements for the year ended March 31, 2025.
- The figures are based on the Audited Standalone financial statements for the year ended March 31, 2025 of Betex India Limited and Swasti Vinayaka Synthetics Limited from the Annual reports of the Companies available from the website of the Stock Exchange and website of the Companies.
- CMP of the peer group is as per the closing price as available on www.bseindia.com
- P/E Ratio for the peer has been computed based on the closing market price of respective equity shares as on March 05, 2026 sourced from website of Stock Exchange as divided by the Basic/diluted EPS as applicable.

6. Financial KPI of our Company

Particulars	₹ in Lakhs			
	November 30, 2025	March 2025	March 2024	March 2023
Revenue from operations ⁽¹⁾	2608.41	3517.30	1111.22	1490.27
Total Income ⁽²⁾	2,628.20	3550.41	1270.10	1506.24
EBITDA ⁽³⁾	735.23	671.68	124.24	48.65
EBITDA (%) Margin ⁽⁴⁾	27.97%	18.92%	11.29%	3.23%
Profit after Tax ⁽⁵⁾	508.58	446.80	81.98	25.25
Current Ratio ⁽⁶⁾	1.97	1.94	0.77	0.54
Debt Equity Ratio ⁽⁷⁾	0.15	0.24	0.75	1.16
Debt Service Coverage Ratio ⁽⁸⁾	42.92	4.48	1.77	4.02
Return on Capital Employed (%) ⁽⁹⁾	31.99%	37.56%	35.11%	19.03%
Net profit Ratio (%) ⁽¹⁰⁾	19.50%	12.70%	7.38%	1.69%
Return on Equity (%) ⁽¹¹⁾	31.15%	56.72%	52.64%	32.32%

As certified by the Statutory auditor vide their certificate dated March 07, 2026 bearing UDIN: 26142660UDF8336.

Notes:

- Revenue from operations is calculated as the sum of revenue from sale.
- Total income is calculated as the sum of revenue from operations and other income for the period/year.
- Operating EBITDA refers to earnings before interest, taxes, depreciation, amortisation, gain or loss from discontinued operations and exceptional items.
- Operating EBITDA Margin refers to EBITDA during a given period as a percentage of Total Income during that period.
- Profit / (loss) for the period/ year is calculated as Total Income less Total Expenses plus Share of (loss) from joint ventures (Net of tax) less Total Tax expenses for the period/ year.
- Current Ratio is a liquidity ratio that measures our ability to pay short-term obligations (those which are due within one year) and is calculated by dividing the current assets by current liabilities.
- Debt to equity ratio is calculated by dividing the debt (i.e., borrowings (current and non-current) and current maturities of long-term-borrowings) by total equity (which includes issued capital and all other equity reserves).
- Debt Service Coverage Ratio is calculated by dividing the sum of Profit after Tax and interest amount by sum of the repayment of loan and interest.
- RoCE (Return on Capital Employed) (%) is calculated as profit before tax plus finance costs divided by total equity plus Reserves & Surplus.
- Net Profit Ratio/Margin quantifies our efficiency in generating profits from our revenue and is calculated by dividing our net profit after taxes by our total revenue.
- Return on equity (RoE) is equal to profit for the year divided by the total equity during that period and is expressed as a percentage

PROPOSED LISTING: TUESDAY, JUNE 02, 2026

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended, wherein 2% (not more than 50% of the Net Issue) shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, 46.47 (not less than 15% of the Net Issue) shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders of which (a) one third of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size of more than two lots and upto such lots equivalent to not more than ₹ 10 lakhs and (b) two thirds of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size exceeding ₹10 lakhs provided under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other subcategory of Non-Institutional Portion and 46.47 (not less than 35% of the Net Issue) shall be available for allocation to Individual Investors who applies for minimum application size in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders, are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of IIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCBS or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent

Continued to next page.....

खबर कोना

सुरक्षा चिंताओं के कारण मेरूसी की प्रतिमा होगी स्थानांतरित

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 1 जून।

कोलकाता के लेक टाउन में फुटबाल के दिग्गज लियोनेल मेरूसी की विशाल प्रतिमा को हटाने और दूसरी जगह ले जाने की तैयारी सोमवार से शुरू हो गई, क्योंकि अधिकारियों ने इस संरचना को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा घोषित कर दिया था। व्यस्त वीआइपी रोड कारिडोर पर स्थित इंजीनियर और कर्मचारी प्रारंभिक कार्य करते देखे गए, जहां पांच महीने पहले ही 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी। यह कदम स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि तेज हवाओं के दौरान विशाल संरचना हिलती हुई प्रतीत होती है, जिससे इसकी स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया कई चरणों में की जाएगी।



पेरिस : फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिका के जैसरी स्नाज्का के खिलाफ इटली के फ्लोरिया कोबोली शाट खेलते हुए।

भारतीय टीम ने अंडर 18 हाकी एशिया कप में कोरिया को हराया

काकाभिगाहारा, 1 जून (भाषा)।

कप्तान केतन कुशवाहा के दो गोलों की बदौलत भारतीय पुरुष अंडर-18 हाकी टीम ने सोमवार को एशिया कप के फूल-ए मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कुशवाहा ने तीसरे और 36वें मिनट में गोल दामे, जबकि वरिंदर सिंह (पांचवां मिनट) और शाहरुख अली (54वां मिनट) ने भी एक-एक गोल किया। कोरिया के लिए कप्तान यून जेह्योक ने 21वें मिनट में एकमात्र गोल किया। इस जीत के साथ भारत छह अंकों के साथ कोरिया और जापान की बराबरी पर पहुंच गया। दोनों पूलों से शीर्ष दो टीमों सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी।

सेरेना 44 वर्ष की उम्र में पेशेवर टेनिस में वापसी को तैयार

पेरिस, 1 जून (एपी)।

अमेरिका की दिग्गज सेरेना विलियम्स लगभग चार वर्ष तक खेल से दूर रहने के बाद 44 साल की उम्र में आगामी क्वीन्स क्लब टूर्नामेंट से पेशेवर टेनिस में वापसी करेंगी। तैरेस बार की ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन सेरेना इस ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट में युगल वर्ग के जरिए प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी करेंगी। डब्ल्यूटीए ने सोमवार को घोषणा की कि सेरेना ने टूर्नामेंट में खेलने के लिए वाइल्ड कार्ड स्वीकार कर लिया है। वहीं क्लब टूर्नामेंट अगले सोमवार से शुरू होगा। उस समय उन्होंने टेनिस को अलविदा कहने की बात तो की थी, लेकिन संन्यास शब्द का इस्तेमाल करने से बचते हुए कहा था कि वह टेनिस से आगे बढ़ रही हैं। सेरेना 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताबों के अलावा 14 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब भी जीत चुकी हैं।

खराब रोशनी से निपटने को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किया बदलाव

टेस्ट क्रिकेट में गुलाबी गेंद के इस्तेमाल को मिली मंजूरी

अहमदाबाद, 1 जून (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) के बोर्ड ने खराब रोशनी के कारण खेल प्रभावित होने की स्थिति में टेस्ट मैचों में परीक्षण के आधार पर गुलाबी गेंद के इस्तेमाल और ड्रिक्स ब्रेक के दौरान मुख्य कोच को मैदान पर जाकर खिलाड़ियों से चर्चा करने की अनुमति देने जैसे कई महत्वपूर्ण बदलावों को अपनी वार्षिक बैठक में मंजूरी दे दी। अहमदाबाद में आयोजित दो दिवसीय बैठक में आइसीसी बोर्ड ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों के चलते क्रिकेट कनाडा की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का भी फैसला किया। इसके साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के चुनावों की निगरानी के लिए आइसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइसीसी के बयान के अनुसार, दोनों टीमों की पूर्व सहमति से टेस्ट मैचों में गुलाबी गेंद के इस्तेमाल का परीक्षण किया जाएगा, ताकि खराब रोशनी की आशंका होने पर अधिक से अधिक खेल संभव हो सके।

मैच की शुरुआत पारंपरिक लाल गेंद से होगी, लेकिन यदि रोशनी कम हो जाती है तो प्लडलाइट्स की मदद से गुलाबी गेंद का इस्तेमाल कर उन ओवरों को पूरा कराया जा सकेगा। मौजूदा नियमों के तहत एक दिन में 90 ओवर फेंके जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 75 ओवर लाल गेंद से खेले जाने के बाद रोशनी कम हो जाए और 15 ओवर बाकी हों, तो दोनों टीमों की पूर्व सहमति होने पर उन ओवरों को दुधिया रोशनी में गुलाबी गेंद से पूरा कराया जा सकेगा। यह देखना



क्रिकेट

खिलाड़ियों के हितों की रक्षा और राष्ट्रीय टीमों के विकास को ध्यान में रखते हुए आइसीसी की निगरानी में नियंत्रित वित्तीय व्यवस्था के तहत क्रिकेट कनाडा को स्वीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। **आइसीसी** क्रिकेट कनाडा को सदस्यता बहाली के लिए आवश्यक शर्तों की सूची भी सौंपेगा। इन शर्तों के अनुपालन की निगरानी आइसीसी नामलाइजेशन कमेटी करेगी।

आइसीसी बोर्ड ने खराब रोशनी के कारण खेल का नुकसान कम करने के लिए मैच अधिकारियों और मैदानों में प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी नई तकनीकों पर शोध को भी मंजूरी दी है। इस अनुसंधान एवं विकास परियोजना को आइसीसी और एमसीसी संयुक्त रूप से वित्तपोषित करेंगे।

दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम इस व्यवस्था को स्वीकार करती है या नहीं। भारतीय खिलाड़ी घरेलू परिस्थितियों में गुलाबी गेंद से टेस्ट खेलने को लेकर पहले भी अनिच्छा जता चुके हैं। गुलाबी गेंद से सीम मूवमेंट अधिक मिलने के कारण मैच का रुख बदल सकता है। आइसीसी बोर्ड ने खराब रोशनी के कारण खेल का नुकसान कम करने के लिए मैच अधिकारियों और मैदानों में प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी नई तकनीकों पर शोध को भी मंजूरी दी है। इस अनुसंधान एवं विकास परियोजना

खेल नियमों में आइसीसी ने संशोधन करते हुए मुख्य कोच या उनके प्रतिनिधियों को निर्धारित ब्रेक के दौरान मैदान पर जाकर खिलाड़ियों से रणनीतिक चर्चा करने की अनुमति दे दी है। टी20 क्रिकेट में टाइम आउट के दौरान कोचिंग स्टाफ के मैदान पर आने की व्यवस्था पहले से लागू है।

को आइसीसी और मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) संयुक्त रूप से वित्तपोषित करेंगे। आइसीसी ने खेल नियमों में संशोधन करते हुए मुख्य कोच या उनके प्रतिनिधियों को निर्धारित ड्रिक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर जाकर खिलाड़ियों से रणनीतिक चर्चा करने की अनुमति दे दी है। टी20 क्रिकेट में रणनीतिक टाइम आउट के दौरान कोचिंग स्टाफ के मैदान पर आने की व्यवस्था पहले से लागू है और अब इसी तरह की सुविधा टेस्ट क्रिकेट में भी उपलब्ध होगी।

प्रधानमंत्री ने एशियाई एथलेटिक्स में 19 पदक जीतने पर भारतीय टीम को सराहा

नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण पदकों सहित 19

पदक जीतने वाले भारतीय टीम को बधाई देते हुए सोमवार को कहा कि यह शानदार प्रदर्शन खिलाड़ियों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाता है।

भारत ने हांगकांग में आयोजित की गई चार दिवसीय प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतकर चीन (14 स्वर्ण, नौ रजत, दो कांस्य) के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण पदकों सहित 19 पदक जीतने के लिए

भारतीय टीम को हार्दिक बधाई। यह उत्कृष्ट प्रदर्शन भारत के युवा एथलीटों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाता है। उम्मीद है कि यह उपलब्धियां आने वाले वर्षों में और भी कई युवा भारतीयों को खेल में अपना करिअर बनाने के लिए प्रेरित करेंगी।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी भारतीय टीम को बधाई दी। शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम को बधाई। 10 स्वर्ण पदकों सहित 19 पदक जीतने की आपकी उपलब्धि भारत की अपार खेल प्रतिभा का प्रमाण है, जो पूरे देश के अनगिनत खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी।

अंडर20 चैंपियनशिप



मुकाबला

सैन फ्रांसिस्को में डब्ल्यूएनबीए बास्केटबाल के पहले हाफ में गोल्डन स्टेट वाल्कीरीज की वेरोनिका बर्टन (दाएं) व लास वेगास एसेस की स्टेफनी टैलबोट गेंद के लिए जूझती हुई।

इंग्लैंड से आज भारतीय महिला टीम की भिड़ंत कप्तान हरमनप्रीत कौर निकालेंगी मध्यक्रम की समस्याओं का समाधान

टांटन, 1 जून (भाषा)।

भारतीय टीम मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार को तीसरे और निर्णायक महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में उतरेगी तो उसे दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष जैसी भरोसेमंद बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी, ताकि टीम अपने मध्यक्रम की समस्याओं का समाधान तलाश सके। भारतीय टीम ने इस श्रृंखला का विजयी आगाज किया था, लेकिन इंग्लैंड ने दूसरा टी20 मुकाबला जीतकर शानदार वापसी की। इस महीने 12 जून से शुरू होने वाले महिला टी20 विश्व कप से पहले दोनों टीमों जीत के साथ अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहेंगी। भारतीय टीम के लिए यह श्रृंखला आगामी विश्व कप से पहले इंग्लैंड की परिस्थितियों में अपने सर्वश्रेष्ठ संयोजन को परखने का भी महत्वपूर्ण अवसर है। चोट से वापसी कर रही यासिनका भाटिया ने पहले टी20 में अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन दूसरे मैच

तीसरा टी20 क्रिकेट

जेमिमा रोड्रिग्स ने भी एक अर्धशतक लगाया, जबकि स्मृति मंधाना और आक्रामक सलामी बल्लेबाज शोफाली वर्मा ने दूसरे मैच में अच्छी शुरुआत की थी। **रोड्रिग्स** ने महिला सुपर लीग में खेलने के अपने अनुभव का लाभ उठाने की उम्मीद जताते हुए कहा कि इस मैदान की पिच आम तौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहती है।

में वह तेजी से रन बनाने में नाकाम रहें और 33 रन के निजी स्कोर पर रिटायर्ड आउट हो गईं। जेमिमा रोड्रिग्स ने भी एक अर्धशतक लगाया, जबकि स्मृति मंधाना और आक्रामक सलामी बल्लेबाज शोफाली वर्मा ने दूसरे मैच में अच्छी शुरुआत की थी। दोनों ही मुकाबलों में भारतीय

टीम अंतिम पांच ओवरों में अपनी लय बनाए रखने में असफल रही। बड़े शाट खेलने के लिए जानी जाने वाली ऋचा घोष अभी तक अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ सकी हैं। पहले मैच में यासिनका और जेमिमा की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 7 विकेट पर 188 रन का स्कोर खड़ा किया था।

भारतीय जोड़ी ने पहली बार जीता सिंगापुर ओपन खिताब

बैडमिंटन

टूर्नामेंट आज से, सिंधु महिला एकल में बुसानन से भिड़ेंगी

सात्विक-चिराग की इंडोनेशिया ओपन के खिताब पर निगाह

जकार्ता, 1 जून (भाषा)।

सिंगापुर ओपन में लंबे समय से चले आ रहे खिताबी इंटरनैट को समाप्त करने के बाद आत्मविश्वास से भरपूर भारत की स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी अब मंगलवार से शुरू हो रहे इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 में लगातार दूसरा खिताब जीतने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगी।

पूर्व विश्व नंबर एक भारतीय जोड़ी को प्रतियोगिता में चौथी वरीयता मिली है। अपने पहले मुकाबले में उनका सामना मलेशिया के कांग खाई शिंग और आरोन ताई की जोड़ी से होगा। सात्विक और चिराग ने एक गेम से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए इंडोनेशिया के फजर अलिफयान और मुहम्मद शोहिबुल फिकरीकी पुरुष युगल



फाइनल में हराकर अपना पहला सिंगापुर ओपन खिताब जीता था। यह जीत भारतीय जोड़ी के लिए इसलिए भी ऐतिहासिक रही क्योंकि वे सिंगापुर ओपन में युगल वर्ग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। उल्लेखनीय है कि सिंगापुर ओपन से

महिला एकल में भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु अपने अभियान की शुरुआत थाईलैंड की बुसानन ऑंगबामरुंगफान के खिलाफ करेंगी। **सात्विक** और चिराग ने एक गेम से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए इंडोनेशिया के फजर अलिफयान और मुहम्मद शोहिबुल फिकरीकी पुरुष युगल फाइनल में हराकर अपना पहला सिंगापुर ओपन खिताब जीता था।

पहले उनका पिछला खिताब 2024 का थाईलैंड ओपन ही था। इसके बाद वे चार बार फाइनल में पहुंचे, लेकिन हर बार उपविजेता रहना पड़ा। पुरुष युगल में भारत की दूसरी जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्माकरुणान का मुकाबला

वैभव सूर्यवंशी ने दिग्गजों को पछाड़कर जीती 'आरेंज कैप'

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 1 जून।

आइपीएल का यह सत्र अपने समापन के साथ कई ऐतिहासिक यादें छोड़ गया है। सत्र के सबसे बड़े स्टार राजस्थान रायल्स के पंद्रह वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा रनों का इतिहास रचते हुए आरेंज कैप अपने नाम की। वैभव ने सर्वाधिक 776 रन बनाए। इसके साथ ही वह आइपीएल इतिहास में आरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।

वैभव ने सत्र में रिकार्ड 72 छक्के उड़ाकर सुपर सिक्सस, 237.3 के स्ट्राइक रेट के लिए सुपर स्ट्राइकर और इमर्जिंग प्लेयर आफ द सीजन के पुरस्कारों पर भी कब्जा जमाया। दूसरी ओर, गेंदबाजी में पंजाब किंग्स के कागिसो रबाडा ने धारदार गेंदबाजी करते हुए 29 विकेट चटकए और पर्पल कैप अपने नाम की। उपविजेता टीम के कप्तान शुभमन गिल को साढ़े बारह करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। कैच आफ द सीजन : मनीष पांडे (बैकवर्ड पाईट पर टिम डेविड का शानदार कैच)। डोट गेंदों का खिताब मोहम्मद सिराज को मिला। उन्होंने सबसे ज्यादा 172 डाट गेंदें निकालीं। सबसे ज्यादा चौके लगाने का खिताब साईं सुदर्शन (75 चौके) के नाम रहा। सर्वश्रेष्ठ पिच व मैदान का खिताब क्रिकेट एसोसिएशन आफ बंगाल और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (4 या कम मैचों के लिए) को मिला।

इस बार विजय जुलूस नहीं : रायल चैलेंज बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया है। बंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त सीमंथ कुमार सिंह ने कहा, हम किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं देंगे। यदि कोई जश्न मनाना चाहता है तो वह घर के अंदर मना सकता है।

आइपीएल 2026



रजत पाटीदार ने ट्राफी भगदड़ पीड़ितों को समर्पित की

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने आइपीएल में अपना दूसरा खिताब जीतने के बाद ट्राफी को पिछले साल भगदड़ में मारे गए प्रशासकों को समर्पित किया है। पाटीदार ने रविवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल में पांच विकेट की जीत के बाद कहा की निश्चित तौर पर बहुत बुरा लगता है कि खिताब जीतने के बाद हमने अपने प्रशासकों को खो दिया। सिर्फ प्रशासक ही नहीं वे तो इस टीम के परिवार के सदस्य थे। उन्होंने कहा की मैं यह ट्राफी उन्हें समर्पित करना चाहता हूं। बस इतना ही। उस भावना को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। दुःख घटनाक्रम के बाद चिन्तास्वामी स्टैडियम में लगभग आठ महीने तक शीर्ष स्तर के क्रिकेट मैचों का आयोजन नहीं किया गया।

JOIN OUR PAID SERVICE – 2026

Daily PDF Access | Editorial Bonus | Almost All Editions

ENGLISH NEWSPAPERS

The Hindu, Indian Express, Hindustan Times, Business Line, Business standard, The Live Mint, Times of India, Telegraph, New Indian Express, Asian Age, Statesman, Tribune, Pioneer, Financial Express, The Economic Times, Mid-Day, Deccan Chronicle, Employment News, Free Press Journal, Hans India, Deccan Herald, Lokmat Times, Mirror, Telangana Today

🎁 Bonus Included :

- ✓ The Hindu Analysis
- ✓ Editorial Complation
- ✓ The Hundu in Hindi

HINDI NEWSPAPERS

दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, बिज़नेस स्टैण्डर्ड, राजस्थान पत्रिका, हरी भूमि, लोकसत्ता, पायनियर, दैनिक ट्रिब्यून, द हिन्दू, राष्ट्रीय सहारा, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, जनसत्ता, देशबंधू, प्रभात खबर, दैनिक नवज्योति, आईनेक्स्ट लाइव, लोकमत, नव भारत, नई दुनिया

🎁 Bonus Included :

- ✓ The Hindu Analysis
- ✓ Editorial Complation
- ✓ The Hundu in Hindi

🔑 Full Package : All in One Plan

The Hindu Plan

(Starter) 1 Month = ~~199~~ ₹99
(★ Popular) 6 Month = ~~599~~ ₹349
(👑 Best Value) 1 Year = ~~999~~ ₹549

Special Offer

You will Get

- ✓ 20+ Hindi Newspapers
- ✓ 22+ English Newspapers
- ✓ THE Hindu, BL,IE,TOI,ET, etc..
- ✓ Dainik Jagran, NBT, DB, Etc..
- ✓ Editorial Complation (En & Hi)
- ✓ The Hindu Analysis

You Get All Editions of These Premium Newspapers

🔑 The Hindu, BL, IE, NIE Plan

The Hindu Plan

(Starter) 1 Month = ~~149~~ ₹69
(★ Popular) 6 Month = ~~499~~ ₹269
(👑 Best Value) 1 Year = ~~799~~ ₹399

Special Offer

You will Get

- ✓ The Hindu (TH)
- ✓ Business Line (BL)
- ✓ Indian Express (IE)
- ✓ New Indian Express (NIE)
- ✓ Editorial Complation
- ✓ The Hindu Analysis

You Get All Editions of These Premium Newspapers

Order
Now



LIMITED TIME
OFFER

Telegram Access Available

→ CLICK HERE &
JOIN NOW

